EDU TERIA
E - D.N.A
Daily Newspaper Analysis
Prelims Mains Essay
By- Nikhil Ranjan

Useful For Prelims

Date: 22 December 2025

तैयारी

ब्राडबैंड की रफ्तार बढ़ेगी

अगली पीढ़ी के संचार उपग्रह का प्रक्षेपण 24 को

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के आगामी 'एलवीएम3 एम6 मिशन' के तहत 24 दिसंबर को 'ब्लू बर्ड ब्लाक-2' उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह मिशन अमेरिका में स्थित एएसटी स्पेसमोबाइल के साथ हुए वाणिज्यिक समझौते का हिस्सा है। इस ऐतिहासिक मिशन के तहत अगली पीढ़ी के संचार उपग्रह को तैनात किया जाएगा, जिसे दुनिया भर में सीधे स्मार्टफोन तक हाई-स्पीड सेल्युलर ब्राडबैंड उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है।

एएसटी स्पेसमोबाइल (एएसटी एंड साइंस, एलएलसी) पहला और एकमात्र अंतरिक्ष-आधारित सेलुलर ब्राडबैंड नेटवर्क विकसित कर रहा है, जो सीधे स्मार्टफोन के माध्यम से सुलभ है और वाणिज्यिक व सरकारी दोनों अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि हम आज लगभग छह अरब मोबाइल उपभोक्ताओं को हो रही 'कनेक्टिविटी' की समस्या को दूर करने और उन अरबों लोगों तक ब्राडबैंड सुविधा पहुंचाने के मिशन पर हैं जो अब भी इंटरनेट से जुड़े नहीं हैं।

इसरो का एलवीएम3 मिशन

इस ऐतिहासिक मिशन के तहत अगली पीढ़ी के संचार उपग्रह को तैनात किया जाएगा, जिसे दुनिया भर में सीधे स्मार्टफोन तक हाई-स्पीड सेल्युलर ब्राडबैंड उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी ने कहा कि हम आज लगभग छह अरब मोबाइल उपभोक्ताओं को हो रही 'कनेक्टिविटी' की समस्या को दूर करने और उन लोगों तक ब्राडबैंड सुविधा पहुंचाने के मिशन पर हैं जो अब भी इंटरनेट से जुड़े नहीं हैं।

एएसटी स्पेसमोबाइल ने सितंबर 2024 में पांच उपग्रह ब्लू बर्ड 1-5 प्रक्षेपित किए थे, जो अमेरिका और कुछ अन्य चुनिंदा देशों में निरंतर इंटरनेट कवरेज को सक्षम बनाते हैं। अमेरिका में स्थित इस कंपनी ने अपने नेटवर्क सपोर्ट को और मजबूत करने के लिए इसी तरह के और उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है तथा इसके लिए दुनिया भर के 50 से अधिक मोबाइल आपरेटर के साथ साझेदारी की है। आगामी मिशन के तहत, एएसटी स्पेसमोबाइल अपने अगली पीढ़ी के संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लाक-2 को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है, जिसे 24 घंटे दुनिया भर में सीधे स्मार्टफोन तक हाई-स्पीड सेल्युलर ब्राडबैंड उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है।

इसरो के अनुसार, यह मिशन न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड और एएसटी स्पेसमोबाइल (एएसटी एंड साइंस, एलएलसी) के बीच हुए समझौते के तहत एक समर्पित वाणिज्यिक प्रक्षेपण होगा। न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, बंगलुरु में स्थित इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। ब्लूबर्ड ब्लाक-2 मिशन वैश्विक लो अर्थ आर्बिट (एलईओ) में उपग्रहों के समूह का हिस्सा है जिसका उद्देश्य उपग्रह के माध्यम से सीधे मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

Jansatta Page No-2

आज भी गणितज्ञों का मार्गदर्शन करते हैं रामानुजन के हजारों समीकरण

महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म 1887 में आज ही तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। गणित में गहरी रुचि की वजह से स्कूल के समय ही कालेज स्तर का गणित हल करने लगे। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में प्रमेय लिखना शुरू किया। उनके शोध कार्यों से प्रभावित होकर 1914 में प्रोफेसर हार्डी ने उन्हें कैंब्रिज यूनिवर्सिटी बुला लिया। 1918 में वह रायल सोसायटी के फेलो चुने गए। 26 अप्रैल, 1920 को उनका निधन हो गया। रामानुजन द्वारा लिखे गए हजारों समीकरण आज भी दुनिया भर के गणितज्ञों का मार्गदर्शन करते हैं।

Dainik Jagaran Page No-14

पहल | मानसून सत्र में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विवि विधेयक 2025 पारित हुआ था, कौशल विश्वविद्यालय अभी दशरथ मांझी श्रम अध्ययन संस्थान से संचालित हो रहा

बिहार के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए कौशल विश्वविद्यालय शुरू हुआ

अलविदा 2025

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के युवाओं को रोजगार पाने में सक्षम बनाने के लिए बड़ी पहल हुई है। युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें अलग-अलग विधाओं में दक्ष बनाने का काम शुरू हुआ है। इसके लिए राज्य सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है।

कौशल विश्वविद्यालय अभी दशरथ मांझी श्रम अध्ययन संस्थान से संचालित हो रहा है। कुलपति की नियुक्ति हो चुकी है। पाठ्यक्रम तैयार करने के बाद जल्द ही प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया जाएगा। इस विश्वविद्यालय के स्थापित होने के बाद राज्य के युवाओं को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का काम शुरू किया जा रहा है। इससे प्रदेश में उद्यमशीलता, व्यावसायिक शिक्षा, शोध और नवाचार को बढ़ावा देना है। सरकार का जोर युवाओं को हुनरमंद बनाने पर है ताकि वे स्वरोजगार भी कर सकें। इसके लिए राज्य सरकार ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का अलग से गठन भी कर लिया है। अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य राज्य सरकार ने निर्धारित किया है। इसके लिए प्रदेश में 50 लाख करोड़ निवेश कराने पर सरकार का जोर है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में कौशल विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विश्वविद्यालय के जरिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं के कौशल विकास से जुड़े कोर्स संचालित करने वाले संस्थानों को यह विश्वविद्यालय संबद्धता प्रदान करेगा। इसी वर्ष मानसून सत्र में विधान मंडल से जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित हुआ था। इसके बाद इसका गजट प्रकाशित हुआ। मुख्यमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। 30 सितंबर 2025 को श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद को इस विश्वविद्यालय का पहला कुलपति बनाया गया।

05 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है राज्य सरकार का

100 एकड़ में कैंपस होगा

कौशल विश्वविद्यालय के स्थायी कैंपस के लिए भी भूमि की तलाश शुरू कर दी गई है। श्रम एवं संसाधन विभाग के द्वारा पटना के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर सौ एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।

उद्योग के लिए तैयार होंगे युवा

राज्य में औद्योगिक इकाइयां लगनी शुरू हो गई हैं। अलग-अलग क्षेत्रों के उद्योग के लिए हुनरमंद युवाओं की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। कौशल विवि के जरिए इन उद्योगों के लिए कुशल कामगार तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा जो युवा रोजगार के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वे भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कामगारों को अच्छे वेतन पर नौकरी मिल जाएगी।

सर्वाधिक मांग वाले तैयार किए जा रहे पाठ्यक्रम

विवि में आधुनिक और सर्वाधिक मांग वाले पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसमें डिग्री और डिप्लोमा के पाठ्यक्रम होंगे। नये साल से पाठ्यक्रम की शुरुआत की जानी है। इसके लिए जनवरी, 2026 में ही देशभर के दर्जनभर कौशल विश्वविद्यालयों और इससे जुड़े संस्थानों के प्रतिनिधियों का पटना में सेमिनार आयोजित होगा।

युवाओं को इंटर्नशिप के लिए भेजा जा रहा

मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत भी इसी साल हुई। इसके तहत राज्य के युवाओं को सरकार इंटर्नशिप करा रही है। अगले पांच सालों में एक लाख पांच हजार युवाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 40 करोड़ 69 लाख की स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी है। इस योजना की शुरुआत भी कर दी गई है। अब-तक 70 हजार से अधिक युवाओं ने अपना पंजीकरण इसके लिए कराया है। युवाओं को इंटर्नशिप कराने के लिए 400 से अधिक कंपनियों ने रुचि दिखायी है। इसके पोर्टल पर जाकर युवा अपने पसंद की तीन कंपनियों का चयन कर सकेंगे।

Hindustan Page No-1

मशरूम उत्पादकों को सस्ती बिजली मिलेगी

राहत

- व्यावसायिक के बदले खेती की श्रेणी में शामिल होंगा मशरूम उत्पादन
- कंपनी ने विनियामक आयोग को दिया प्रस्ताव, एक अप्रैल से आदेश प्रभावी

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य में मशरूम की खेती करने वाले किसानों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। मशरूम उत्पादक किसानों को अब तक व्यवसायिक दर पर बिजली मिल रही है।

कंपनी ने मशरूम की खेती करने वालों को सामान्य किसानों की तरह ही सस्ती बिजली देने का निर्णय लिया है। कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को यह प्रस्ताव दिया है। आयोग की मुहर लगी तो एक अप्रैल से मशरूम उत्पादक किसानों को सस्ती बिजली मिलने लगेगी।

कंपनी के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अभी मशरूम उत्पादक किसानों को व्यवसायिक (गैर घरेलू) श्रेणी में माना जाता है। इसके अनुसार ग्रामीण व शहरी इलाके की बिजली दर अलग-अलग है। ग्रामीण इलाकों में मशरूम उत्पादक किसानों को एक से सौ यूनिट तक खपत करने पर 3.35 रुपए प्रति यूनिट तो 100 यूनिट से अधिक खपत होने पर 4.21 रुपए प्रति यूनिट की अनुदानित दर से बिजली का भुगतान करना पड़ता है, जबकि शहरी इलाके में पांच किलोवाट तक के मशरूम उत्पादक किसानों को 5.67 रुपए प्रति यूनिट की अनुदानित दर से बिजली बिल का भुगतान करना होता है। पांच से 70 किलोवाट तक के कनेक्शन में किसानों को 100 यूनिट तक 5.67 रुपए जबकि इससे अधिक खपत होने पर 6.44 रुपए प्रति यूनिट की अनुदानित दर के हिसाब से बिजली बिल देना होता है। वहीं, कंपनी के प्रस्ताव के अनुसार मशरूम की खेती करने वाले किसानों को सामान्य किसानों की तरह ही मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से ही बिजली बिल देना होगा। यानी आगामी एक अप्रैल से मशरूम उत्पादन करने वाले किसानों को मौजूदा दर की तुलना में कई गुना सस्ती बिजली मिलेगी। इसका लाभ किसानों को होगा। मशरूम उत्पादन करने को लेकर किसानों में आकर्षण बढ़ेगा और उनकी आय में सुधार होगा।

देश में अग्रणी उत्पादक राज्य है बिहार

बिहार में मशरूम की खेती की स्थिति अच्छी है। राज्य अब देश का अग्रणी उत्पादक बन गया है। देश में हो रहे उत्पादन में 11 फीसदी का योगदान बिहार का है। बिहार ने ओडिशा को पछाड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य सरकार पहले ही अन्य मदों में मशरूम की खेती करने वाले किसानों को 90 फीसदी तक सब्सिडी देती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। गया जी, भोजपुर जैसे जिले मशरूम उत्पादन में प्रमुख केंद्र बन गए हैं।

Hindustan Page No-1

बेंगलुरु में रविवार को आयोजित बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन-3 में भाग लेते बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, 'लेट्स इंस्पायर बिहार' के मुख्य संरक्षक आईपीएस विकास वैभव व अन्य। • हिन्दुस्तान

बिहार में उद्योग लगाने का अनुकूल वातावरण तैयार : दिलीप जायसवाल

- बेंगलुरु में कहा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए बीआईएसएफ का होगा गठन

पटना, हिटी। उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार में उद्योग लगाने और नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छ, पारदर्शी और अनुकूल वातावरण तैयार है। आने वाले वर्षों में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देकर बिहार में एक करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान कराना है। राज्य में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल (बीआईएसएफ) के गठन की प्रक्रिया चल रही है।

डॉ. जायसवाल रविवार को बेंगलुरु में विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने की दिशा में 'लेट्स इंस्पायर बिहार' अभियान की ओर से आयोजित 'बिहार 2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन-3 को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर कर रहे थे। बीआईएसएफ का उद्देश्य बिहार भर में उद्यमियों, निवेशकों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करना, संस्थागत संरक्षण सुनिश्चित करना और औद्योगिक वातावरण में विश्वास व स्थिरता को और अधिक सुदृढ़ करना है। यह कार्यक्रम द ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बिहार और प्रवासी समुदाय से जुड़े 1200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें लगभग 900 उद्यमी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, आईटी प्रोफेशनल्स, विचारक और स्टार्टअप प्रतिनिधि शामिल रहे। कार्यक्रम में विधायक मिथिलेश तिवारी और राजीव रंजन सिंह बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। इस अभियान के मुख्य संरक्षक आईपीएस विकास वैभव ने कहा कि बिहार से पलायन की गति को रोकने और राज्य में ही व्यापक रोजगार सृजन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

Hindustan Page No-1

सौ साल पुरानी कोडाइकनाल सौर वेधशाला से नई जानकारी मिली | शोध | दुनिया का सबसे वृहद सौर डेटासेट उपलब्ध है

सूर्य के रहस्यों को सुलझाने में मदद मिली

चेन्नई, 21 दिसंबर (भाषा)।

सौ साल पुरानी कोडाइकनाल सौर वेधशाला में वर्षों से एकत्रित दैनिक सौर प्रेक्षणों से सूर्य की चुंबकीय गतिविधि में अक्षांशों के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के बारे में नई जानकारी मिली है।

इस खोज से अंतरिक्ष-मौसम पूर्वानुमान और जलवायु माडल में भी मदद मिल सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अधीन स्वायत्त निकाय भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आइआइए) के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन में सूर्य के प्रकाश की कैल्शियम-के रेखा में कैप्चर किए गए 11 वर्षों (2015-2025) के स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा का विश्लेषण किया गया। यह स्पेक्ट्रल सिग्नेचर सूर्य के क्रोमोस्फीयर में बहुत ऊपर बनता है और चुंबकीय गतिविधि के संवेदनशील मार्कर के रूप में कार्य करता है। शोध के लेखकों में शामिल अपूर्व श्रीनिवास ने समाचार एजंसी को बताया कि सूर्य पर किए गए सभी अध्ययन अंततः अंतरिक्ष मौसम को समझने के लिए आवश्यक हैं, जिसका पृथ्वी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए, जितना अधिक हम समझेंगे, संभावित व्यवधानों और आपदाओं के लिए हम उतनी ही बेहतर तैयारी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हाल में निरंतर अवलोकन के 125 वर्ष पूरे करने वाली कोडाइकनाल सौर वेधशाला में दुनिया का सबसे वृहद सौर डेटासेट उपलब्ध है। श्रीनिवास के अनुसार, शोध टीम ने इस समृद्ध संग्रह का इस्तेमाल यह पता लगाने के लिए किया कि सूर्य की चुंबकीय तीव्रता अक्षांशों में कैसे बदलती है - जिससे उच्च गतिविधि के लगातार क्षेत्र सामने आए, जो सूर्य के 11-वर्षीय सनस्पाट शिखर चक्र के अनुरूप हैं।

शोध के लेखकों में शामिल अपूर्व श्रीनिवास ने बताया कि सूर्य पर किए गए सभी अध्ययन अंततः अंतरिक्ष मौसम को समझने के लिए आवश्यक हैं, जिसका पृथ्वी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। *वर्ष* 1899 में स्थापित कोडाइकनाल सौर वेधशाला सूर्य के बदलते स्वरूप को प्रतिदिन दर्ज करती है और दुनिया के सबसे लंबे और सबसे सुसंगत सौर अभिलेखों में से एक को संरक्षित करती है।

अध्ययन के प्रमुख लेखक केपी राजू ने कहा कि सूर्य आग का स्थिर गोला नहीं है, बल्कि चुंबकीय रूप से सक्रिय तारा है, जो गतिविधि के व्यापक चक्रों का अनुसरण करता है। आइआइए के पूर्व प्रोफेसर ने कहा कि सूर्य को अक्षांशीय पट्टियों में विभाजित करके और प्रत्येक से आने वाले एकीकृत प्रकाश का विश्लेषण करके, हम उन पैटर्न को उजागर कर सकते हैं, जो सूर्य के धब्बों जैसी अलग-अलग विशेषताओं का अध्ययन करते समय अदृश्य होते हैं।

टीम ने पाया कि अधिकांश चुंबकीय गतिविधि 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच केंद्रित होती है, जिसमें 15 डिग्री से 20 डिग्री के आसपास स्पष्ट शिखर होते हैं, जो उन क्षेत्रों से मेल खाते हैं, जहां सूर्य के धब्बे सबसे अधिक बार होते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि आंकड़ों की ऐसी निरंतरता दुर्लभ है और इससे वैश्विक सौर अनुसंधान में भारत के वैज्ञानिक समुदाय को असाधारण बढ़त मिलती है। 1899 में स्थापित कोडाइकनाल सौर वेधशाला सूर्य के बदलते स्वरूप को प्रतिदिन दर्ज करती है और दुनिया के सबसे लंबे और सबसे सुसंगत सौर अभिलेखों में से एक को संरक्षित करती है।

Jansatta Page No-11

घटना ने बढ़ाई संरक्षण और प्राचीन विरासत को लेकर चिंता | संकट | कारणों का पता लगाने के लिए आइआइटी मुंबई ने की जांच

लोनार झील का जलस्तर बढ़ने से कई प्राचीन मंदिर जलमग्न

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध लोनार झील का जलस्तर पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ने के कारण उसके आस पास स्थित प्राचीन मंदिर जलमग्न हो गए हैं। इस घटना ने झील के संरक्षण और प्राचीन विरासत को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कारणों का पता लगाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मुंबई के विशेषज्ञों की मदद ली है।

करीब 50,000 साल पहले उल्कापिंड के टकराने से बनी यह झील दुनिया की सबसे बड़ी 'बेसाल्टिक प्रभाव क्रेटर' झील है। बेसाल्टिक प्रभाव क्रेटर झील पृथ्वी की बेसाल्ट (बेसाल्टिक

घटना ने झील के संरक्षण और प्राचीन विरासत को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कारणों का पता लगाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मुंबई के विशेषज्ञों की मदद ली है।

चट्टानों) वाली सतह पर किसी उल्कापिंड या क्षुद्रग्रह के टकराने से बने गड्ढे में बनती है। 'रामसर साइट' (अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों) के रूप में मान्यता प्राप्त यह स्थान अपने खारे-क्षारीय पानी और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है।

'रामसर साइट' रामसर सम्मेलन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की एक आर्द्रभूमि होती है, जिसे वर्ष 1971 में यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) द्वारा स्थापित एक अंतर-सरकारी पर्यावरण संधि 'आर्द्रभूमि पर सम्मेलन' के रूप में भी जाना जाता है और इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है, जहां उस वर्ष सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यहां करीब 1,200 साल पुराने कई मंदिर स्थित हैं, जिनमें से प्रसिद्ध कमलजा देवी मंदिर सहित कई अन्य संरचनाएं बढ़ते जलस्तर के कारण पानी में डूब गई हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ), नागपुर सर्कल के अधीक्षक पुरातत्वविद् अरुण मलिक ने बताया कि झील के निचले घेरे में 15 मंदिर हैं, जो एएसआइ के दायरे में आते हैं। पिछले पांच-छह वर्षों से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे प्राचीन मंदिरों को खतरा पैदा हो गया है। शोध में यह बात सामने आई है कि आसपास संरक्षित वन क्षेत्र विकसित होने और पौधरोपण बढ़ने से सूक्ष्म पर्यावरण में बदलाव आया है, जिससे क्षेत्र में जल धारण क्षमता बढ़ी हो सकती है। मलिक के अनुसार, एएसआइ कमलजा मंदिर के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार (एप्रन वाल) और चबूतरा बनाने की योजना बना रहा है, जिससे जलस्तर बढ़ने पर भी मंदिर सुरक्षित रहे और श्रद्धालु वहां तक पहुंच सकें।

बुलढाणा के जिलाधिकारी किरण पाटिल ने बताया कि झील में पानी की निकासी का कोई मार्ग नहीं है, जबकि गोमुख मंदिर जैसे प्राकृतिक झरनों से पानी का प्रवाह लगातार बना हुआ है।

हाल के वर्षों में बारिश के स्वरूप में बदलाव आया है और इस साल लोनार में अत्यधिक भारी बारिश देखी गई। आइआइटी मुंबई के विशेषज्ञों ने नमूने लिए हैं और वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह प्राकृतिक बदलाव किस वजह से हो रहा है और इसका पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा। स्थानीय शोधकर्ताओं और पर्यावरणविदों ने भी इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस अद्वितीय 'क्रेटर' का संरक्षण अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में 'क्रेटर' के भीतर कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है और पूरी गतिविधि पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है।

Jansatta Page No-11

केंद्र ने अरावली पर्वतमाला में खनन को बढ़ावा देने के आरोप को खारिज किया, कहा

संरक्षित क्षेत्र में आ जाएगा 90 फीसद इलाका

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

केंद्र सरकार ने रविवार को उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि बड़े पैमाने पर खनन की अनुमति देने के लिए अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में बदलाव किया गया है। सरकार ने अरावली पर्वतीय क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का हवाला देते हुए यह बात कही।

इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित एक प्रारूप पर्वतीय प्रणाली की मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है और एक व्यापक प्रबंधन योजना को अंतिम रूप दिए जाने तक नए खनन पट्टों पर रोक लगाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सुंदरबन बाघ अभयारण्य में बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित परिभाषा से अरावली क्षेत्र का 90 फीसद से अधिक हिस्सा संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। सरकार ने सौ मीटर के मापदंड को लेकर चल रहे विवाद के बीच जारी स्पष्टीकरण में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों

सरकार ने सौ मीटर के मापदंड को लेकर चल रहे विवाद के बीच जारी स्पष्टीकरण में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर अरावली पहाड़ियों और पर्वत शृंखला की परिभाषा को सभी राज्यों में मानकीकृत किया गया है ताकि अस्पष्टता को दूर किया जा सके और दुरुपयोग को रोका जा सके।

पर अरावली पहाड़ियों और पर्वत शृंखला की परिभाषा को सभी राज्यों में मानकीकृत किया गया है ताकि अस्पष्टता को दूर किया जा सके और दुरुपयोग को रोका जा सके। विशेष रूप से वे प्रथाएं जिनके कारण पहाड़ियों के आधार के बेहद करीब खनन जारी रखना संभव हुआ।

पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में अवैध खनन से संबंधित काफी समय से लंबित मामलों की सुनवाई करते हुए मई 2024 में एक 'समान परिभाषा' की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया था। पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित इस समिति में राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के प्रतिनिधियों के साथ-साथ तकनीकी निकायों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

समिति ने पाया कि केवल राजस्थान में ही एक औपचारिक रूप से स्थापित परिभाषा है, जिसका वह 2006 से पालन कर रहा है। इस परिभाषा के अनुसार, स्थानीय भू-भाग से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भू-आकृतियों को पहाड़ियां माना जाता है और ऐसी पहाड़ियों को घेरने वाली सबसे निचली सीमा रेखा के भीतर खनन निषिद्ध है, चाहे उस रेखा के भीतर की भू-आकृतियों की ऊंचाई या ढलान कुछ भी हो। सूत्रों ने बताया कि चारों राज्य इस लंबे समय से चली आ रही राजस्थान की परिभाषा को अपनाने पर सहमत हो गए हैं, साथ ही इसे वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी बनाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को भी शामिल किया गया है।

इन उपायों में एक-दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर स्थित पहाड़ियों को एक ही पर्वत शृंखला मानना, किसी भी खनन निर्णय से पहले भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्रों पर पहाड़ियों और पर्वत शृंखलाओं का अनिवार्य मानचित्रण और खनन निषिद्ध मुख्य और संरक्षित क्षेत्रों की स्पष्ट पहचान करना शामिल है। सरकार ने 100 मीटर से नीचे के क्षेत्रों में खनन की अनुमति दिए जाने के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि यह प्रतिबंध संपूर्ण पहाड़ी प्रणालियों और उनके भीतर स्थित भू-आकृतियों पर लागू होता है, न कि केवल पहाड़ी के शिखर या ढलान पर।

Jansatta Page No-8

भारत 2027 एशियाई कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर सका | हताशा | बांग्लादेश, हांगकांग और सिंगापुर से मिली हार

भारतीय फुटबाल के लिए निराशा से भरा रहा वर्ष 2025

नई दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय फुटबाल के लिए वर्ष 2025 निराशा से भरा रहा जिसमें उसे गंभीर प्रशासनिक संकट, अदालती सुनवाई, वित्तीय समस्याओं, घरेलू लीग के अभाव और सीनियर पुरुष टीम के खराब प्रदर्शन से जूझना पड़ा। जैसे-जैसे साल खत्म होने लगा लियोनेल मेस्सी के बहुचर्चित 'जीओएटी इंडिया टूर' ने कुछ दिलचस्पी पैदा की और इस खेल को लेकर कुछ चर्चा शुरू करने पर मजबूर किया। लेकिन इससे भारतीय फुटबाल को कुछ फायदा हुआ होगा ऐसा नहीं लगता है।

भारतीय फुटबाल की अपनी समस्याएं ही कम नहीं थी और ऐसे में मेस्सी के दौरे के पहले दिन साल्ट लेक स्टेडियम में फैली अराजकता और अव्यवस्था ने शर्मिंदगी को और बढ़ा दिया।

इस साल भारत की सीनियर पुरुष टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। उसे ढाका में नवंबर में खेले गए 2027 एएफसी एशियाई कप क्वालीफाइंग मैच में बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा। यह बांग्लादेश के खिलाफ पिछले 22 वर्षों में उसकी पहली पराजय थी। भारतीय टीम पिछले साल अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई थी।

भारतीय फुटबाल के गढ़ कहे जाने वाले कोलकाता में कानून-व्यवस्था का बिगड़ना भले ही अच्छी खबर न हो, लेकिन हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में मेस्सी के कार्यक्रम अच्छी तरह से आयोजित किए गए। इस साल भारत की सीनियर पुरुष टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। उसे ढाका में नवंबर में खेले गए 2027 एएफसी एशियाई कप क्वालीफाइंग मैच में बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा। यह बांग्लादेश के खिलाफ पिछले 22 वर्षों में उसकी पहली पराजय थी।

भारतीय टीम वर्ष 2024 में अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन इस साल वह कुछ जीत हासिल करने में कामयाब रही, जिसमें सितंबर में मध्य एशियाई देशों ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आयोजित सीएएफए नेशंस कप में कांस्य पदक जीतना भी शामिल है। सबसे अहम मैचों में भारत अपेक्षित प्रदर्शन करने में विफल रहा और 2011 के बाद पहली बार एशियाई कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर सका, जिससे टीम फीफा रैंकिंग में और नीचे खिसक गई। बांग्लादेश के अलावा भारतीय पुरुष टीम को हांगकांग और सिंगापुर जैसी कम रैंकिंग वाली टीमों से भी हार का सामना करना पड़ा। सिंगापुर से 1-2 से मिली हार ने एशियाई कप में प्रवेश करने की उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

Jansatta Page No-18

सफलता की पहली सीढ़ी संकल्प

खुमानसिंह चुंडावत

मनुष्य के जीवन में योगासन, ध्यान, प्राणायाम और सभी प्रकार के आध्यात्मिक अभ्यास केवल शरीर को लचीला या मन को शांत ही नहीं करते, वे हमारे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाते हैं, जो हमें लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। यदि थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, तो पता चलता है कि हमने जीवन में अब तक जो कुछ भी पाया है, या आगे जो कुछ भी पाना चाहते हैं, उसकी जड़ में केवल एक ही तत्व काम करता है, और वह है संकल्प।

संकल्प का बीजारोपण

शिक्षा और ज्ञान केवल जानकारी का प्रसार नहीं है, यह व्यक्ति के भीतर एक दिशा, एक दृष्टिकोण और एक उद्देश्य का बीज बोती है। जब एक छात्र पढ़ाई करता है, वह केवल परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा होता वह अपने भीतर आत्मविश्वास, संकल्प और भविष्य की पहचान गढ़ रहा होता है। यही छात्र आगे चलकर चिकित्सक, अभिनेता, साहित्यकार, वैज्ञानिक या उद्यमी बनता है और इन सभी की सफलता की पहली नींव होती है: दृढ़ संकल्प।

युवा पीढ़ी की दुविधा

आज की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी चुनौती संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि दिशा की कमी है। दुविधा अक्सर उत्साह के अभाव से पैदा होती है, जबकि जीवन में आगे बढ़ने का पहला कदम उत्साह से ही उठता है। जब मन उत्साहित होता है, विचार स्पष्ट होते हैं, ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होती है, निर्णय दृढ़ बनते हैं। उत्साह और संकल्प ही वह संगम है, जहाँ से सफलता की राह शुरू होती है।

संकल्प का आध्यात्मिक पक्ष

आध्यात्मिक दृष्टि से संकल्प केवल मानसिक इच्छा नहीं, बल्कि चेतना का सशक्त अंतर्निहित केंद्र है। जितना उच्च, पवित्र और निस्वार्थ संकल्प होगा, उतनी अधिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसके साथ खड़ी होती है। मान्यता है कि जब संकल्प निर्मल हो, उद्देश्य स्पष्ट हो, और भाव सकारात्मक हो, तब सृष्टि स्वयं उस संकल्प की पूर्ति में सहयोगी बन जाती है।

पश्चिमी विचारधारा ने इसे आकर्षण का नियम कहा है। जब व्यक्ति मन, बुद्धि और विश्वास को एक दिशा में लगा देता है, तो आकर्षण का सिद्धांत उसे परिणाम तक ले आता है। भारतीय संस्कृति में यह सिद्धांत सहस्राब्दियों से अस्तित्व में है। हमारे शास्त्रों में 'तथास्तु' देवता का वर्णन इसी सत्य का रूपांतरण है। जब कोई मनुष्य सच्चे मन से शुभ संकल्प करता है, तो प्रकृति

सार-संसार

कहती है: 'तथास्तु! ऐसा ही हो!' यही भावना लोक परंपराओं, कथाओं, मंत्रों और आशीर्वादों में सदियों से गूंजती रही है।

1. अपनी दिशा स्वयं तय करें, 2. पहला कदम पूरे उत्साह से उठाएं, 3. अपने संकल्प को स्पष्ट, पवित्र और अडिग बनाएं : जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं, तो साधारण मनुष्य भी असाधारण ऊंचाइयां छू लेता है। संकल्प कीजिए, उत्साह जगाइए, जीवन स्वयं राह बना देगा। वास्तव में, प्रत्येक व्यक्ति एक चलायमान ऊर्जा केंद्र है। उसके भीतर अनंत संभावनाओं और अकल्पनीय ऊर्जा का भंडार होता है। यह ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित होगी, यही तय करता है कि उसका जीवन किस दिशा में बढ़ेगा। यदि यह ऊर्जा नकारात्मक सोच और भ्रमित भावनाओं में उलझ जाती है, तो जीवन जड़ता, तनाव और निराशा की ओर अग्रसर होता है। इसके विपरीत, जब यही ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होती है, तो वह व्यक्ति के भीतर उत्साह, प्रसन्नता और नए संकल्पों का संचार करती है।

इस अंतर्निहित ऊर्जा को जागृत और गतिशील बनाने के लिए आवश्यक है कि सकारात्मक क्रियाओं से अपने भीतर उत्साह और जीवंतता को बनाए रखें। उत्साह और प्रसन्नता दो मूल गुण हैं, जो व्यक्तित्व के विकास के द्वार खोलते हैं। ये दोनों गुण एक-दूसरे के पूरक हैं। जहां उत्साह होता है, वहां प्रसन्नता स्वतः आती है और जहां प्रसन्नता होती है, वहां उत्साह भी सहज रूप से जन्म लेता है। जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि हम उत्साह और प्रसन्नता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। यही गुण हमारे संकल्पों को दिशा देते हैं और हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। वस्तुतः सफलता: संकल्प का ही परिणाम है। वास्तविक सफलता कोई चमत्कारी घटना नहीं होती। असाधारण यह है कि व्यक्ति अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचाने, उसे सकारात्मक दिशा दे और अपने संकल्पों व उत्साह के बल पर जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना ले। ऐसा व्यक्ति न केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करता है, बल्कि वह स्वयं भी आनंद और प्रेरणा का स्रोत बन जाता है।

रचनात्मक जीवनधारा

मानव जीवन निरंतर प्रगति और सृजन की ओर प्रवाहित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य रचनात्मक शक्ति निहित होती है। किंतु प्रायः लोग किसी नए प्रयास की शुरुआत से पहले अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। यह एक सामान्य धारणा है कि जब तक संसाधन, साधन और सहयोग उपलब्ध नहीं होते, तब तक किसी प्रयास की नींव नहीं रखी जा सकती। लेकिन जीवन का सत्य इससे भिन्न है, परिस्थितियां पहले से तैयार नहीं मिलतीं। वे तो हमारे संकल्प और प्रयासों के साथ-साथ आकार लेती हैं। संकल्प ही वह शक्ति है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना सकती है। जब व्यक्ति का उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो सारा अस्तित्व उसके पक्ष में सक्रिय हो जाता है।

Jansatta Page No-7

अपने को स्वयं ऊपर उठाओ

अम्बिका कुशवाहा अम्बी

आज मनुष्य का जीवन एक अंतहीन प्रतिस्पर्धा बन गया है, जहां हर व्यक्ति बस एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा है। इस जीवन-प्रतिस्पर्धा की दौड़ में हम हर रोज असंख्य समस्याओं से जूझते हैं और बार-बार असफलताओं को गले लगाते हैं। उदाहरण के लिए, एक युवा जो दिन-रात किताबों में डूबा रहता है, जिसके लिए चौबीस घंटों में दिन और रात का अंतर मिट गया है। वह बस इस जिद्द में लगा है कि जिंदगी की परीक्षा के बीच किताबों की परीक्षा में कामयाब हो जाए। इस दौड़ में हम यह भूल गए हैं कि जीवन जीने का असली मकसद क्या है, खुशी, संतोष, मानवता और आत्म-जागरूकता।

इस प्रतिस्पर्धा ने इंसान के जीवन को एक बोझ बना दिया है। जीवन में संघर्ष और असफलता के बीच लोगों के ताने, उपहास, और श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ का अंतर उसकी आत्मा में कील की तरह ठोकते हैं। उसके समय और मेहनत की कद्र कोई भी नहीं करता, बल्कि असफलता के जख्म को और गहरा किया जाता है। यही कारण है कि युवाओं में मानसिक तनाव और आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस सामाजिक दबाव का सबसे भयावह परिणाम है मानसिक स्वास्थ्य का संकट। युवा, जो जीवन की शुरुआत में ही सपनों और उम्मीदों से भरे होते हैं, इस दबाव में टूटने लगे हैं। आत्महत्या, जो कभी हमारे समाज में दुर्लभ थी, अब एक भयानक 'सामान्यता' बनती जा रही है। मानसिक तनाव, अवसाद, और आत्मविश्वास की कमी अब केवल शब्द नहीं, बल्कि लाखों जिंदगियों की

जीवन जीने का नाम

प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ ने न केवल व्यक्तियों को, बल्कि पूरे समाज को एक ऐसे रास्ते में धकेल दिया है, जहां हर कदम पर मूल्यांकन और तुलना का डर साये की तरह साथ चलता है। यह दौड़ केवल उपलब्धियों की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और मानवीय संवेदनाओं की भी हार बन चुकी है।

हकीकत हैं।हम भारतीय, जो कभी पारिवारिक और सामाजिक संतोष एवं सामुदायिक एकता की पहचान रखते थे, आज प्रतिस्पर्धा के युग का पर्याय बन गए हैं। स्कूलों में बच्चों के बीच नंबरों की होड़ है, नौकरियों में तरक्की की दौड़ है, और जो जीत गया, वही समाज की नजर में ज्ञानी और सिकंदर है, लेकिन इस होड़ में हारा हुआ व्यक्ति समाज की नजर में अयोग्य और मूर्ख है।

इस प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ ने न केवल व्यक्तियों को, बल्कि पूरे समाज को एक ऐसे रास्ते में धकेल दिया है, जहां हर कदम पर मूल्यांकन और तुलना का डर साये की तरह साथ चलता है। यह दौड़ केवल उपलब्धियों की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और मानवीय संवेदनाओं की भी हार बन चुकी है। हमारी संस्कृति, जो कभी वसुधैव कुटुंबकम् के सिद्धांत पर गर्व करती थी, आज व्यक्तिगत जीत और सामाजिक श्रेष्ठता के पीछे भाग रही है। इस प्रक्रिया में, हमने न केवल अपनी सामुदायिक एकता खो दी, बल्कि अपने भीतर की उस शांति को भी दांव पर लगा दिया, जो हमारे इंसान होने का गवाह थी। आज इंसान दूसरों से तुलना करके स्वयं को तनावग्रस्त कर रहा है। यह तुलना केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक भी है। माता-पिता अपने बच्चों को पड़ोसी के बच्चे से बेहतर देखना चाहते हैं, और समाज सफलता को भौतिक उपलब्धियों से मापता है, महंगा घर, लग्जरी कार, या सोशल मीडिया पर हजारों लाइक्स। सोशल मीडिया ने इस आग में घी डालने का काम किया है। इस तुलना ने हमें न केवल असंतुष्ट बनाया है, बल्कि हमारी मानसिक शांति भी छीन ली है। इंसान भूलते जा रहा है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग मंजिल होती है।

जिंदगी में कामयाब होने के लिए इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में हम अनेक विपरीत परिस्थितियों और संघर्षों से अकेले ही जूझते हैं। जरूरी नहीं कि हर इंसान को इस संघर्ष में किसी का साथ मिले या आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिले। ऐसे में व्यक्ति को स्वयं के भीतर सकारात्मक सोच विकसित करनी होगी। उसे स्वयं को ऊर्जावान और साहसी बनाना होगा, ताकि वह विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित न हो और बहादुरी से आगे बढ़ सके। जब हम स्वयं के सारथी बन जाते है, तब कोई भी चीजें हमारे मनोबल को कमजोर नहीं कर सकती है।

भारतीय दर्शन हमें इसकी प्रेरणा देता है। भागवत गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं, 'उद्धरेदात्मनात्मानम्' यानी अपने आप को स्वयं ऊपर उठाओ। इस सूत्र की सीख है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर ही है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, 'अपने आप पर विश्वास करो, और तुम पूरी दुनिया को जीत सकते हो।' आधुनिक मनोविज्ञान भी आंतरिक प्रेरणा को सिखाता है, 'जब हम अपने मूल्यों और उद्देश्य से जुड़ते हैं, तो बाहरी तुलना हमें डिगा नहीं सकती।'

Jansatta Page No-7

विकसित भारत - जी राम जी विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को 'विकसित भारत –जी राम जी' विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। विपक्ष के विरोध के बीच संसद ने वीबी–जी राम जी विधेयक, 2025 को पारित किया था। इसका उद्देश्य मौजूदा ग्रामीण रोजगार कानून 'मनरेगा' को प्रतिस्थापित करना है और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वित्त वर्ष 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करना है। सरकार के अनुसार, इस नई योजना का लक्ष्य 'विकसित भारत–2047' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है।

अब यह विधेयक कानून बन गया है। यह अब 20 साल पुराने कानून मनरेगा की जगह लेगा। नए कानून के तहत ग्रामीण मजदूरों को 100 के बदले 125 दिन का रोजगार मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह जानकारी दी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, यह विधेयक मनरेगा की जगह लेगा और इसे विकसित भारत 2047 की दृष्टि के अनुरूप तैयार किया गया है। सरकार का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में आय सुरक्षा को मजबूत करने के साथ टिकाऊ और उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, ताकि समावेशी और संतुलित विकास को बढ़ावा मिल सके। कानून के प्रावधानों के तहत इच्छुक ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 125 दिन का रोजगार देना सरकार की वैधानिक जिम्मेदारी होगी। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों के अंदर करना अनिवार्य किया गया है। तय समयसीमा के भीतर भुगतान नहीं होने पर देरी का मुआवजा देने का भी प्रावधान रखा गया है।

गुरुवार को संसद में विपक्ष के विरोध के बीच 'जी राम जी' विधेयक पारित हुआ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका और कृषि उत्पादकता को मजबूत करना है। इसके साथ ही स्थानीय नियोजन, श्रमिक सुरक्षा और योजनाओं के एकीकरण पर जोर दिया गया है। इस कानून का मकसद ग्रामीण आय सुरक्षा को मजबूत करना, अग्रिम पंक्ति की योजनाओं का एकीकरण और कृषि–रोजगार संतुलन है।

Jansatta Page No-8

जागरण विशेष

अब एप से किसान जान सकेंगे फसल की सेहत

जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने बनाया सरल एप, आसान होगी खेती

अनुज सक्सेना • जागरण

रुद्रपुर: किसानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण सामने आई है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने एक ऐसा एप विकसित किया है, जो बोआई से लेकर कटाई तक फसल से संबंधित हर तरह की जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध कराएगा। यह एप स्थान, भौगोलिक परिस्थिति और मौसम की जानकारी के आधार पर कार्य करेगा। विज्ञानियों की टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) का उपयोग करते हुए इस एप का नाम 'सरल-एप' रखा है। इसका ट्रायल अंतिम चरण में है और नए साल से यह देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले किसानों के लिए उपलब्ध होगा।

विश्वविद्यालय के एग्रो मेट्रोलाजी विभाग के प्राध्यापक डा. अजीत सिंह नैन के निर्देशन में मृदा विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा. अरविंद त्यागी और शस्य विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा. अजय श्रीवास्तव की टीम ने सरल-एप तैयार कर लिया है। डा. नैन बताते हैं कि अभी तक गूगल एप समेत कई माध्यम से किसानों को फसल और मौसम की जानकारी सामान्यतया मिल ही जाती है, लेकिन सरल-एप पूरी तरह सटीक होगा। यह किसी किसान को सिर्फ उसी की फसल, स्थान और वहां के मौसम के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी बताने में सक्षम होगा।

रुद्रपुर में खेत में ट्रैक्टर से जुताई करते किसान • जागरण आर्काइव

नासा के डाटा से सटीक जानकारी देगा एप

डा. अजीत सिंह नैन बताते हैं कि इसमें नासा का डाटा उपलब्ध होगा। इसके साथही, एआइ और जीपीएस सिस्टम भी शामिल रहेगा। जीपीएस सिस्टम किसान के खेत की लोकेशन को पहचानने में मदद करेगा। नासा का सर्वर मौजूदा मौसम का डाटा देगा और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) से अगले पांच दिनों का मौसम पूर्वानुमान प्राप्त होगा। इन सभी सूचनाओं के आधार पर एप किसान को बताएगा कि अच्छी उपज के लिए उसे कब क्या करना है। हर पांचवें दिन यह अपडेट किसान को घर बैठे ही प्राप्त होगा।

डा. नैन के मुताबिक, हर क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां, मौसम का प्रभाव व खेत की उर्वरा स्थिति अलग-अलग होती है। हर खेत की सेहत अलग होती है। ऐसे में अभी तक कोई एप ऐसा नहीं था जो हर खेत, उसमें उगाई जा रही फसल, मौसम और उस फसल की सेहत जानकर उसकी उत्पादकता की भी जानकारी किसान को दे सकता हो। नया एप किसान को बताएगा कि कब खाद डालनी है, कब कितना पानी देना है, कब दवा आदि का छिड़काव करना है और कटाई कब कर लेनी है। एप के अनुसार काम करने पर अंत में यह भी किसान को पता चल सकेगा कि जिस तरह एप के मार्गदर्शन में वह खेती कर रहा है उससे उसे कितनी फसल प्राप्त हो जाएगी।

> कृषि क्षेत्र में विश्वविद्यालय के विज्ञानी लगातार नए शोध में जुटे हैं। इसी कड़ी में सरल-एप का विकास किया गया है। इससे देश के किसी भी हिस्से से किसान अपने खेत, फसल और उत्पादकता की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह एप देश में अपनी तरह का पहला है। विज्ञानियों की टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई।
>
> **डा. मनमोहन सिंह चौहान**, कुलपति

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

Dainik Jagaran Page No-6

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मुहर लगते ही देश में नया कानून लागू

मंजूरी: जी राम जी से 125 दिनों के रोजगार की गारंटी

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रविवार को 125 दिन की रोजगार गारंटी वाले विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही यह विधेयक अब वीबी-जी राम जी कानून बन गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बयान में कहा, यह कानून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेगा और भारत की ग्रामीण रोजगार व विकास व्यवस्था में एक निर्णायक सुधार है। सरकार के अनुसार, नया कानून 'विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करता है। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन की मजदूरी वाला रोजगार देने का प्रावधान है। इसकी अधिसूचना भी राजपत्र में जारी कर दी गई है।

वीबी-जी राम जी कानून में खेती के बुआई और कटाई के मौसम को ध्यान में रखते हुए राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में कुल 60 दिन का नो-वर्क पीरियड अधिसूचित करने का अधिकार भी दिया गया है, ताकि कृषि श्रम की उपलब्धता प्रभावित न हो।

मनरेगा की जगह ग्रामीण रोजगार का नया मॉडल

सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को मनरेगा से आगे ले जाते हुए 'वीबी-जी राम जी' कानून लागू किया है। सरकार का दावा है कि इसका उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि आय सुरक्षा, टिकाऊ अवसंरचना और जलवायु अनुकूल विकास को एक साथ जोड़ना है। यह कानून ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप नया स्वरूप देता है।

60 दिन का नो-वर्क पीरियड बुआई-कटाई के मौसम में

15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य

रोजगार को चार प्राथमिक क्षेत्रों से जोड़ा

1. जल सुरक्षा
2. ग्रामीण अवसंरचना
3. आजीविका से जुड़ा ढांचा
4. जलवायु अनुकूल कार्य

मजबूत निगरानी और जवाबदेही

- योजना में जो काम होगा, उनका डिजिटल रिकॉर्ड एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा।
- योजना का निर्माण विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के जरिए होगा
- प्रशासनिक खर्च सीमा 6% से बढ़ाकर 9%
- बेहतर स्टाफिंग, प्रशिक्षण और तकनीकी क्षमता
- केंद्र-राज्य साझेदारी मॉडल (60:40)
- ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 से जोड़ा गया

मजदूरी में विलंब पर मुआवजा भी देना होगा

मंत्रालय ने कहा, यह कानून ग्रामीण रोजगार को केवल एक कल्याणकारी योजना न रखकर, उसे विकास का एक समग्र साधन बनाने की दिशा में कदम है। इसमें रोजगार को जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़े ढांचे और चरम मौसम से निपटने वाले कार्यों से जोड़ा गया है। कानून के तहत मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह या अधिकतम 15 दिन के भीतर अनिवार्य होगा। देरी पर मुआवजा भी देना होगा। सभी कार्य विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के तहत होंगे और इन्हें पीएम गति शक्ति जैसे राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।

'शांति' विधेयक को भी राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रविवार को 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' (शांति) विधेयक को भी मंजूरी दे दी। अब यह कानून बन गया।

Hindustan Page No-3

2025 में 50 गीगावाट बढ़ी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता

- पूरे वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में दो लाख करोड़ रुपये का निवेश
- सरकार को उम्मीद, 2026 में भी इसी रफ्तार से क्षमता जुड़ेगी

नई दिल्ली, प्रेट्र: वर्ष 2025 में प्रमुख वैश्विक शक्तियों ने नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर कम किया, जबकि इस दौरान भारत ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। इस दौरान भारत की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आने लगा। उसने यह लक्ष्य पेरिस समझौते के तहत तय 2030 की समयसीमा से पांच साल पहले हासिल कर लिया।

दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता अब करीब 510 गीगावाट हो गई है, जिसमें 247 गीगावाट जीवाश्म ईंधन आधारित और 262 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से है। गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों में 254 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से है। भारत ने 2025 में लगभग 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जिसके लिए करीब दो लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया। इससे देश की कुल गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता लगभग 262 गीगावाट तक पहुंच गई। सरकार को उम्मीद है कि 2026 में भी इसी रफ्तार से क्षमता जोड़ी जाएगी। हालांकि भूमि अधिग्रहण और बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) पर हस्ताक्षर में देरी जैसी चुनौतियां नई परियोजनाओं को सीमित कर रही हैं। उद्योग के अनुमान के मुताबिक प्रति मेगावाट निवेश आवश्यकता लगभग चार करोड़ रुपये है। इस तरह 50 गीगावाट क्षमता जोड़ने के लिए करीब दो लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ।

Dainik Jagaran Page No-

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से ज्यादा हुई टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की संपत्ति

जेएनएन, नई दिल्ली: अमेरिका के दिग्गज कारोबारी एलन मस्क की कुल संपत्ति बढ़कर 748.9 अरब डालर हो गई है। यह भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार से भी ज्यादा है। आरबीआइ के अनुसार, 12 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 688.949 अरब डालर रहा है।

दरअसल अमेरिका की डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ही मस्क के 2018 के वेतन पैकेज को बहाल किया है। डेलावेयर की एक कोर्ट ने टेस्ला की ओर से मस्क को दिए वेतन पैकेज को 2024 में रद दिया था। 2018 का पैकेज शुक्रवार को टेस्ला के स्टाक मूल्य के आधार पर लगभग 139 अरब डालर का था। यदि मस्क इस वेतन पैकेज से सभी स्टाक विकल्पों का उपयोग करते हैं, तो उनकी हिस्सेदारी लगभग 12.4 प्रतिशत से बढ़कर 18.1 प्रतिशत हो जाएगी। संपत्ति में इस ताजा वृद्धि ने मस्क को दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनने के और करीब ला दिया है।

एलन मस्क

- 748.9 अरब डालर हुई अमेरिकी कारोबारी की कुल संपत्ति
- डेलावेयर कोर्ट के एक फैसले से 139 अरब डालर बढ़ी संपत्ति

मस्क पिछले सप्ताह ही 600 अरब डालर से ज्यादा की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। फोर्ब्स के अनुसार, बीते सोमवार को उनकी कुल संपत्ति करीब 677 अरब डालर थी। मस्क की संपत्ति में यह उछाल उनकी कंपनी स्पेसएक्स के मूल्यांकन में आइपीओ से पहले बढ़ोतरी की वजह से आया था।

दुनिया के अमीरों में मुकेश अंबानी 16वें स्थान पर

दुनिया के अमीरों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस समय 16वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स के अनुसार, इस समय उनकी संपत्ति 113 .1 अरब डालर है। वहीं, 66.3 अरब डालर की संपत्ति के साथ अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी 27वें स्थान पर हैं।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

Dainik Jagaran Page No-10

सामान ढोने के लिए रुड़की से कलियर के बीच चली भारत की पहली ट्रेन

1851 में आज ही गंग नहर के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री ढोने के लिए उत्तराखंड के रुड़की से पिरान कलियर के बीच भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी। दो बोगियों वाली इस ट्रेन ने 10 किमी की दूरी 38 मिनट में तय की। इसके दो साल बाद 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच पहली यात्री ट्रेन चली।

थामस एडिसन के बल्बों से पहली बार सजाया गया क्रिसमस ट्री

1882 में आज ही थामस एडिसन के सहयोगी एडवर्ड एच जानसन ने अपने घर के क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए एडिसन द्वारा बनाए बल्बों का इस्तेमाल किया था। इससे पहले क्रिसमस ट्री मोमबत्तियों से सजाया जाता था। रोशनी वाली क्रिसमस ट्री जल्द ही पूरी दुनिया में प्रचलन में आ गई।

Dainik Jagaran Page No-14

राष्ट्रीय गणित दिवस

संख्याओं के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन

ब्रजेश कुमार मिश्र

पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, सुल्तानपुर (यूपी)

प्राचीन काल में आर्यभट्ट से लेकर आधुनिक काल में श्रीनिवास रामानुजन तक भारतीय गणितशास्त्र के विकास में एक अद्भुत सातत्य दृष्टिगोचर होता है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भाष्कराचार्य जैसे प्राचीन विद्वानों ने शून्य, दशमलव और संख्या पद्धति का प्रयोग कर गणित और खगोलशास्त्र के क्षेत्र में जो प्रारंभिक काम करना शुरू किया था, श्रीनिवास रामानुजन ने उसे शिखर तक पहुंचाया। संख्याओं के जादूगर के नाम से विख्यात श्रीनिवास रामानुजन का संघर्षमय जीवन उन सभी के लिए एक प्रेरणा है, जो अपनी जिंदगी से हारकर नैराश्यभाव में जी रहे हैं। अभावग्रस्त जीवन में रहकर भी कैसे गुणात्मक श्रेष्ठता प्राप्त की जा सकती है, श्रीनिवास रामानुजन इसके अप्रतिम उदाहरण हैं।

रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के इरोड नामक स्थान पर 22 दिसंबर, 1887 को अत्यंत सामान्य परिवार में हुआ। उनकी जन्मतिथि को "राष्ट्रीय गणित दिवस" के रूप में मनाया जाता है। धनाभाव के कारण कुंभकोणम के एक सरकारी स्कूल में उनका प्रवेश कराकर छात्रवृत्ति की व्यवस्था कराई गई, किंतु गणित के अलावा अन्य विषयों में फेल हो जाने के कारण उनकी छात्रवृत्ति रोक दी गई। गणित में अत्यंत रुचि के कारण उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा और जीएस कार की प्रसिद्ध पुस्तक "सिनोप्सिस आफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स" के अध्ययन के बाद उनका जीवन पूरी तरह गणित को समर्पित हो गया। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उन्होंने न केवल कार के सिद्धांतों और प्रमेयों को सत्यापित किया, बल्कि स्वयं के सिद्धांत और प्रमेय भी विकसित किए। 1911 में पहली बार उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित किए गए प्रमेय और सिद्धांत "इंडियन मैथमेटिकल सोसायटी" में प्रकाशित किए गए। दीर्घवृत्तीय समाकलन, विभाजन और संयोजन विश्लेषण, विशेष फलन और निश्चित समाकलन, अनंत श्रेणी, हाइपरज्यामितीय श्रेणी आदि के संबंध में उनकी मौलिक खोजों ने गणित के बड़े-बड़े महारथियों को पीछे छोड़ दिया।

साल 1913 में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट पर कार्य करने के दौरान श्रीनिवास रामानुजन के एक सहयोगी ने गणित पर उनके द्वारा किए गए शोधों और प्रमेयों को प्रसिद्ध गणितज्ञ और कैंब्रिज विश्वविद्यालय के प्रो. जीएच हार्डी के पास भेज दिया। प्रो. हार्डी रामानुजन के शोधों को देखकर दंग रह गए और उन्होंने साल 2014 में उन्हें इंग्लैंड आने के लिए आमंत्रित किया। इंग्लैंड पहुंचकर श्रीनिवास रामानुजन ने प्रो. हार्डी के साथ मिलकर गणित के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया। इंग्लैंड में दोनों ने मिलकर संख्या सिद्धांत और अनंत श्रृंखलाओं पर कई शोधपत्र प्रकाशित किए। साल 1917 में रामानुजन "लंदन मैथमेटिकल सोसायटी" के सदस्य बनाए गए और 1918 में रायल सोसायटी के फेलो भी चुने गए, जो कि अत्यंत सम्मान की बात थी। रायल सोसायटी की सदस्यता के बाद त्रिनिटी कालेज की फेलोशिप प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय बने। रामानुजन को नंबर थ्योरी अर्थात संख्याओं से विशेष लगाव था और यही कारण है कि उन्हें "संख्याओं के अनन्य साधक" की उपाधि दी जाती है।

आज रामानुजन के शोध कार्यों का भौतिकी, रसायन, कंप्यूटर साइंस एवं दूरसंचार के क्षेत्र में भी सार्थक प्रयोग हो रहा है। रामानुजन ने अपने जीवन काल में करीब 4000 प्रमेय और सूत्र दिए, जो प्रमुखतः अनंत श्रृंखला, संख्या सिद्धांत, माक थीटा फंक्शन आदि से संबंधित हैं। इनमें से कई प्रमेयों को रामानुजन ने स्वयं अपने जीवनकाल में ही सिद्ध कर दिया था, कुछ उनकी मृत्यु के बाद हल किए गए और कुछ पर आज भी रिसर्च चल रहा है। वे गणितीय संख्याओं को इतनी तीव्रता से हल कर देते थे कि लोग उन्हें "संख्याओं का जादूगर" कहने लगे थे।

Dainik Jagaran Page No-9

आजकल

परमाणु ऊर्जा के लिए बड़ी पहल

संसद ने गत दिनों परमाणु ऊर्जा विधेयक पारित कर दिया। इसका उद्देश्य भारत को परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना और ऊर्जा के अन्य स्रोतों पर निर्भरता कम करना है। परमाणु ऊर्जा चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति का विश्वसनीय स्रोत है, जबकि अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों के मामले में ऐसा नहीं है। 2025 में देश ने 8.9 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है और रोडमैप का पालन किया तो 2047 तक 100 गीगावाट की क्षमता हासिल कर लेगा

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

भारत में निजी निवेश से परमाणु ऊर्जा बढ़ाने के किए जा रहे प्रयास। फाइल

संसद ने गत दिनों परमाणु ऊर्जा विधेयक पारित कर दिया। कड़े नियंत्रण वाले असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने का प्रविधान करने वाला यह विधेयक 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट आफ न्यूक्लियर एनर्जी फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया' (शांति) राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही कानून का रूप ले लेगा। इसका उद्देश्य भारत को परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना और ऊर्जा के अन्य स्रोतों पर निर्भरता कम करना है। परमाणु ऊर्जा चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति का विश्वसनीय स्रोत है, जबकि अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों के मामले में ऐसा नहीं है। 2025 में देश ने 8.9 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है और रोडमैप का पालन किया तो 2047 तक 100 गीगावाट की क्षमता हासिल कर लेगा। बड़े पैमाने पर एआइ के आने से भारत की ऊर्जा की जरूरत परमाणु स्रोतों पर बहुत ज्यादा निर्भर होगी। दरअसल भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने की दृष्टि से ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी कंपनियों का सहयोग जरूरी है। अकेली सरकारी संस्थाओं के बूते इस मकसद को पूरा करना मुमकिन नहीं है। अतः इस नए विधेयक के आने से परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद की जा रही है। यह विधेयक परमाणु ऊर्जा के लिए एक सुरक्षित कानूनी ढांचा तैयार करेगा। फलस्वरूप निजी कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर सकेंगी। इस क्षेत्र में अभी तक सरकारी परमाणु ऊर्जा विभाग का ही वर्चस्व है। इस विधेयक के बाद अतिरिक्त बिजली उत्पादन, ग्रिड एकीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विकास होगा।

दरअसल सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को बाधा-मुक्त इसलिए करना चाहती है, जिससे 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सके। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाना चाहती है। इसी कारण वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में लघु परमाणु संयंत्रों के लिए बड़े बजट का प्रविधान किया गया था। इस क्षेत्र में नया प्रयोग करते हुए पहली बार निजी कंपनियों को लघु परमाणु संयंत्र पूरे देश में स्थापित करने का अवसर दिया जाएगा। कालांतर में विदेशी कंपनियों को भी परमाणु संयंत्र लगाने की अनुमति दी जा सकेगी। साथ ही माड्यूलर (प्रतिरूपक) रिएक्टरों के आधुनिकीकरण के लिए शोध और विकास पर भी धनराशि खर्च की जाएगी। परमाणु ऊर्जा में नई प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इसे पीपीपी माडल पर क्रियान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश में स्वच्छ एवं वैकल्पिक बिजली को बढ़ावा देना है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत में छोटे परमाणु संयंत्र लगाने और भारत में ही उनका उत्पादन करने को लेकर समझौता हुआ था।

एआइ के दौर में ऊर्जा की खपत असाधारण रूप से बढ़ने की उम्मीद है। यह एक कंप्यूटर की भाषा का कृत्रिम बुद्धि से जुड़ा माडल है। भाषा माडल ऐसे मशीन लर्निंग माडल होते हैं, जो मानव भाषा के पाठ को समझ भी सकते हैं और सृजित भी कर सकते हैं। ये माडल भाषा के बड़े डाटा भंडार का विश्लेषण करने में भी सक्षम होते हैं। सुपर और क्वांटम कंप्यूटरों में भी इसी एआइ की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता लघु परमाणु संयंत्रों से ही संभव है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में इसे एक क्रांतिकारी पहल माना जा रहा है।

विकसित भारत के लिए ऊर्जा की उपलब्धता एक बड़ी आवश्यकता है। इसलिए सरकार केवल पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। 'आपरेशन सिंदूर' के बाद जिस तरह हमारी सेना ने पाकिस्तान के आतंकी और गैर-सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया था, उन आयुधों के निर्माण और संचालन के लिए भी परमाणु ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इस परिप्रेक्ष्य में सौर और पवन ऊर्जा पर सरकार पहले ही काफी काम कर चुकी है। अतः अब फोकस परमाणु ऊर्जा पर केंद्रित है, क्योंकि इसमें संभावनाएं अधिक हैं। आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऊर्जा सुरक्षा को सरकार की नौ प्राथमिकताओं में शामिल किया था। ऊर्जा परिवर्तन के संबंध में एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करने की बात भी कही गई है। इससे यह तय होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह पारंपरिक ऊर्जा की जगह धीरे-धीरे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का महत्व बढ़ रहा है। यह दस्तावेज ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार, विकास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का भी समाधान खोजेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में निकेल, कोबाल्ट, तांबा और लिथियम जैसी धातुओं के उत्पादों के आयात पर शुल्क घटाया गया है। इन उत्पादों का प्रयोग परमाणु और सौर ऊर्जा सहित अन्य ऊर्जा उत्सर्जन उपायों में भी होता है। आयात सस्ता होने से इनका निर्माण भारत में करना आसान होगा। यही नहीं, परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और अंतरिक्ष एवं रक्षा क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली 25 धातुओं पर सीमा शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। यानी छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के रास्ते साफ किए जा रहे हैं।

भारत में एक और जहां लंबे समय से अटकी परमाणु बिजली परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन शुरू हो रहा है, वहीं निजी निवेश से परमाणु ऊर्जा बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत जिले के तापी-काकरापार में 22,500 करोड़ रुपये की लागत से बने 700-700 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाले दो परमाणु ऊर्जा संयंत्र गत वर्ष राष्ट्र को समर्पित कर दिए। ये देश के पहले स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। ये संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 10.4 अरब यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन करेंगे, जिससे गुजरात के साथ-साथ अन्य राज्यों को भी बिजली की आपूर्ति होगी। ये संयंत्र शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ने की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होंगे। भारत सरकार के उपक्रम परमाणु ऊर्जा निगम ने मध्य प्रदेश में चार नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी है। शीघ्र ही ये संयंत्र नीमच, देवास, सिवनी और शिवपुरी में स्थापित किए जाएंगे। यदि सब कुछ ठीक रहा, तो जल्द ही इन परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। इनके चालू होने पर 1200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता पिछले दस वर्षों में लगभग दोगुनी हो चुकी है और 2031 तक इसके तीन गुना होने की उम्मीद है।

हालांकि परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न खतरों की आशंकाएं भी पूरी तरह बेबुनियाद नहीं हैं। इसलिए परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। रूस के चेर्नोबिल और जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्रों में हुई दुर्घटनाओं के बाद इस तरह की चिंताएं और भी प्रासंगिक हो गई हैं। वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद प्राकृतिक आपदाओं के सामने मानव अब भी असहाय है। जापान में मात्र दस सेकेंड की सुनामी ने फुकुशिमा की वैज्ञानिक उपलब्धियों को चकनाचूर कर दिया था। सृष्टि को संजीवनी देने वाले तत्व-हवा, पानी और अग्नि जब अपनी न्यूनतम मर्यादाओं की सीमा लांघकर भीषण विराटता धारण करते हैं, तो चारों ओर केवल विनाश का दृश्य दिखाई देता है। इसलिए जरूरी है कि परमाणु रिएक्टर प्रदायक कंपनियों पर कड़ी शर्तों के तहत मुआवजे के प्रविधान तय हों या बीमा कंपनियों को दुर्घटना की स्थिति में क्षतिपूर्ति से जोड़ा जाए।

परमाणु बिजली संयंत्रों में शेकाइट का उपयोग माडरेटर के रूप में किया जाता है। इसमें पानी की बहुत थोड़ी मात्रा के विलयन से हाइड्रोजन और आक्सीजन के विखंडन के समय अत्यधिक तापमान के साथ ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा का दबाव टर्बाइनों को तीव्र गति से घुमाता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। रिएक्टरों के इस उच्च तापमान को एक सीमा तक नियंत्रित रखने के लिए उन पर ठंडे पानी की निरंतर तेज धाराएं छोड़ी जाती हैं। हालांकि प्राकृतिक या अन्य आपदा की स्थिति में ये परमाणु संयंत्र अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रणालियों से संचालित और नियंत्रित होने के कारण स्वतः बंद हो जाते हैं, लेकिन इस अवस्था में विरोधाभासी स्थिति यह होती है कि जल से हाइड्रोजन और आक्सीजन का नाभिकीय विखंडन तो रुक जाता है, किंतु रासायनिक प्रक्रियाएं और भौतिक दबाव एकाएक समाप्त नहीं होते।

परिणामस्वरूप जलधारा का प्रवाह बंद होते ही रिएक्टरों का तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। यह तापमान न केवल जीव-जंतुओं को, बल्कि स्टील जैसी ठोस धातु को भी पल भर में पिघला देने में सक्षम होता है। इस दृष्टि से इन संयंत्रों से जुड़े संभावित खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

Dainik Jagaran Page No-9

अमेरिकी सेटेलाइट को बुधवार को अंतरिक्ष में ले जाएगा इसरो का 'बाहुबली' राकेट

चेन्नई, प्रेट्र : अंतरिक्ष क्षेत्र में कई कीर्तिमान रच चुका भारत बुधवार 24 दिसंबर को एलवीएम-3 एम6 मिशन के तहत अमेरिकी सेटेलाइट ब्ल्यूबर्ड-ब्लाक-2 को अंतरिक्ष में ले जाएगा। इसरो का 'बाहुबली' राकेट एलवीएम-3 इस सेटेलाइट को कक्षा में पहुंचाएगा। इस ऐतिहासिक मिशन में अगली पीढ़ी के संचार उपग्रह की तैनाती होगी, जिसे दुनियाभर में स्मार्टफोनों में उच्च गति के सेलुलर ब्राडबैंड पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे दुनियाभर में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और स्मार्टफोन को 4जी और 5जी मोबाइल ब्राडबैंड सेवा सीधे मिल सकेगी। एएसटी स्पेसमोबाइल के साथ हुए वाणिज्यिक समझौते के तहत इस सेटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया जाएगा। लांच व्हीकल मार्क3(एलवीएम3) भारत का सबसे शक्तिशाली राकेट है। इसलिए इस राकेट को बाहुबली राकेट भी कहते हैं।

एएसटी स्पेसमोबाइल (एएसटी एंड साइंस, एलएलसी) कंपनी पहला और एकमात्र अंतरिक्ष-आधारित सेलुलर ब्राडबैंड नेटवर्क बना रही है, जिसका उपयोग स्मार्टफोनों द्वारा सीधे किया जा सकता है। इसे कमर्शियल तथा सरकारी उपयोगों के लिए डिजाइन किया गया है।

कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर कहा, हम लगभग छह अरब मोबाइल उपभोक्ताओं द्वारा सामना की जा रही कनेक्टिविटी की खामियों को समाप्त करने और उन अरबों लोगों तक ब्राडबैंड पहुंचाने के लिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं जो अभी भी ब्राडबैंड से नहीं जुड़े हैं। एएसटी स्पेसमोबाइल सितंबर 2024 में पांच सेटेलाइट (ब्ल्यूबर्ड 1-5) को लांच किया, जो अमेरिका और अन्य कुछ देशों में निरंतर इंटरनेट कवरेज में मदद कर रहे हैं। अमेरिका स्थित इस कंपनी ने अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए इसी तरह के सेटेलाइट को लांच करने की योजना बनाई है। इसने दुनियाभर में 50 से अधिक मोबाइल आपरेटरों के साथ साझेदारी की है।

ब्ल्यूबर्ड ब्लाक-2 में 223 वर्ग मीटर का फेज़्ड एरे है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में तैनात होने वाला सबसे बड़ा कमर्शियल संचार सेटेलाइट है। इसरो के अनुसार इस सेटेलाइट की लांचिंग इसरो की कमर्शियल शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआइएल) के जरिये की जाएगी। इसके लिए एएसटी स्पेसमोबाइल ने एनएसआइएल के साथ करार किया था। ब्ल्यूबर्ड ब्लाक-2 मिशन वैश्विक निम्न पृथ्वी कक्षा के सेटेलाइट के समूह का हिस्सा है, जिससे सेटेलाइट के माध्यम से सीधे मोबाइल कनेक्टिविटी सुविधा मिलेगी।

- अगली पीढ़ी के इस उपग्रह को एएसटी स्पेसमोबाइल के साथ हुए वाणिज्यिक समझौते के तहत किया जाएगा लांच
- स्मार्टफोन को सीधे मिल सकेगी 4जी और 5जी मोबाइल ब्राडबैंड सेवा, दुनियाभर में बढ़ेगी डिजिटल कनेक्टिविटी

2024 में एएसटी स्पेसमोबाइल-5 सेटेलाइट लांच हुआ जो इंटरनेट कवरेज कर रहे

देश का सबसे शक्तिशाली राकेट है लांच व्हीकल मार्क3(एलवीएम3)।

बाहुबली प्रक्षेपण यान की खूबियां

- जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट लांच व्हीकल (जीएसएलवी) एमके3 भी कहा जाता है
- 8000 किलोग्राम तक के पेलोड लोअर अर्थ आर्बिट(एलईओ) में ले जाने में सक्षम
- ब्लूबर्ड ब्लाक-2 एलवीएम3 राकेट से एलईओ में प्रक्षेपित किया जाने वाला सबसे भारी पेलोड होगा
- 2023 में चंद्र मिशन के दौरान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतर चुका है बाहुबली राकेट
- एलवीएम-3 ने चंद्रयान-2 और 72 उपग्रहों के साथ दो वनवेब मिशनों को भी लांच कर चुका है
- तीन चरणों वाला यह राकेट पिछले महीने स्वदेशी संचार उपग्रह सीएमएस-03 को कक्षा में ले गया था।
- 4,410 किलोग्राम वजनी सीएमएस-03 भारत का सबसे भारी स्वदेशी संचार उपग्रह माना जाता है।

अंतरिक्ष से मिसाइल ट्रैकिंग करेगा स्वदेशी स्टार्टअप 'दिगंतर'

प्रथम पृष्ठ से आगे

अंतरिक्ष में मलबे की निगरानी करने वाला भारतीय स्टार्टअप 'दिगंतर', अब अंतरिक्ष से ही मिसाइलों की निगरानी के क्षेत्र में भी कदम रखने जा रहा है। इन दोनों ही कामों में उपग्रहों की मदद ली जाती है। दुनियाभर की सरकारें मिसाइलों ट्रैकिंग की अवधारणा में दिलचस्पी दिखा रही हैं। ये क्षेत्र अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। बेंगलुरु आधारित दिगंतर इंडस्ट्रीज के सहसंस्थापक और सीईओ अनिरुद्ध शर्मा ने बताया कि कंपनी ने इस साल जनवरी में सर्विलांस उपग्रह 'स्काट' लांच किया था। 2026-27 में 15 ऐसे ही उपग्रहों को लांच करने की तैयारी है। साथ ही कंपनी दो अल्बाट्रास उपग्रह भी लांच करेगी, जिससे मिसाइलों का सटीक तरीके से पता लगाया जा सकेगा और समय रहते चेतावनी जारी की जा सकेगी। साथ ही 'स्काईगेट' भी लांच किया जाएगा, जो जमीन आधारित सेंसर का बढ़ता हुआ नेटवर्क है, जो आपरेशनल क्षेत्रों में लगातार निगरानी में मदद करता है।

भारत में अब अंतरिक्ष यात्री बनना सपना नहीं रहा, मेहनत करें युवाः शुभांशु : गगनयात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि भारत में अंतरिक्षयात्री को भी पेशे के रूप में मान्यता मिलने लगी है, जिससे युवाओं के लिए अवसरों की अनंत संभावनाओं का सृजन हुआ है। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित पुणे साहित्य समारोह में शुभांशु ने कहा, मैं छात्रों से कहता हूं कि चंद्रमा पर कदम रखने का लक्ष्य तय करें। उन्होंने कहा, आज हर युवा मुझसे पूछता है कि अंतरिक्ष यात्री कैसे बना जा सकता है। अब, अंतरिक्ष यात्री बनना भी एक पेशा है। अब ये सपना नहीं रह गया है और आप सभी के लिए खुला हुआ है। इसके लिए कठिन मेहनत करें।

Dainik Jagaran Page No-6

इंटरनेट मीडिया पर ज्यादा समय देने से अधीर और उग्र हो रहे बच्चे

नई दिल्ली, जागरण न्यूज नेटवर्कः इंटरनेट मीडिया पर अधिक समय बिताने से बच्चों और किशोरों में मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। अत्यधिक स्क्रीन समय से नींद की गुणवत्ता में कमी, अकादमिक प्रदर्शन में गिरावट और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे अवसाद, चिंता और आत्मविश्वास की कमी के मामले देखे जा रहे हैं। इससे अभिभावक चिंतित हैं और बच्चों के इंटरनेट मीडिया इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी चाहते हैं। लोकल सर्कल्स के सर्वे में 25 प्रतिशत अभिभावक चाहते हैं कि बच्चों के इंटरनेट मीडिया इस्तेमाल से पहले माता-पिता की मंजूरी की अनिवार्यता हो।

देश के आइटी मंत्रालय ने पिछले महीने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) नियम, 2025 को अधिसूचित किया, जिससे बच्चों को इंटरनेट मीडिया के हानिकारक प्रभावों से बचाने की उम्मीदें जगी हैं। इस नए नियम का उद्देश्य बच्चों के डिजिटल डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें सोशल मीडिया एवं ओटीटी प्लेटफार्मों के अनियंत्रित उपयोग से बचाना है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में भारत में 88 करोड़ इंटरनेट यूजर थे, और किशोर औसतन डेढ़ घंटे रोजाना इंटरनेट मीडिया पर बिता रहे थे। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 में यह पाया गया कि 14-16 वर्ष आयु वर्ग के 82.2 प्रतिशत बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग करने में सक्षम हैं, लेकिन इनमें से केवल 57 प्रतिशत इसका इस्तेमाल शिक्षा के लिए करते हैं। इसके विपरीत, 76 प्रतिशत बच्चे सोशल मीडिया के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। यह आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि बच्चों का ध्यान सीखने की तुलना में इंटरनेट मीडिया की ओर अधिक है।

अवसाद से लेकर साइबर बुलिंग तक में फंसे बच्चेः रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 11 से 37 प्रतिशत किशोरों में इंटरनेट मीडिया की लत के लक्षण पाए गए हैं, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षणिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अध्ययन में पाया गया कि तीन से 60 प्रतिशत बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं। बच्चों और किशोरों में बढ़ती डिजिटल लत के मद्देनजर, देशभर के अस्पतालों में 'डिजिटल एडिक्शन क्लीनिक' खोली जाने लगी हैं।

लोकल सर्कल्स का सर्वे

49% शहरी अभिभावक मानते हैं कि उनके बच्चे तीन घंटे से ज्यादा समय इंटरनेट मीडिया पर बिता रहे

25% अभिभावक बच्चों को इंटरनेट मीडिया इस्तेमाल के लिए अनिवार्य अभिभावकीय मंजूरी के पक्ष में

लोकलसर्कल्स को 302 जिलों से 18 से कम आयुवर्ग वाले बच्चों के अभिभावकों से मिलीं 57 हजार प्रतिक्रियाएं

तीन घंटे से ज्यादा समय इंटरनेट पर बिता रहे बच्चे

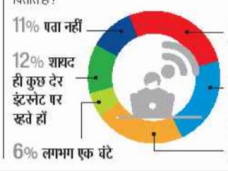

लोकल सर्कल्स के हालिया सर्वे के अनुसार, 49 प्रतिशत शहरी भारतीय माता-पिता का कहना है कि उनके 9-17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे हर दिन औसतन तीन घंटे या उससे अधिक समय इंटरनेट मीडिया पर बिताते हैं। सर्वे में 19,001 माता-पिता से यह सवाल पूछा गया था कि 9-17 वर्ष के बच्चे इंटरनेट पर कितना समय बिताते हैं?

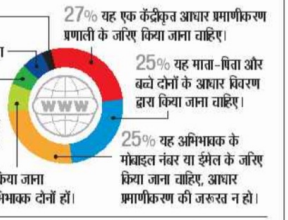

अभिभावकों की राय, बच्चों के लिए हो सख्त पाबंदी

लोकल सर्कल्स के सर्वे में 25 प्रतिशत शहरी अभिभावकों ने कहा कि बच्चों के इंटरनेट मीडिया इस्तेमाल के लिए आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से अनिवार्य माता-पिता की सहमति लागू करनी चाहिए। इस सर्वे में 18,426 अभिभावकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी।

Dainik Jagaran Page No-5

अधिसूचना जारी

अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब व तलवंडी साबो पवित्र शहर घोषित

वाल्ड सिटी में अब नहीं बेच सकेंगे मांस, तंबाकू पदार्थ और शराब, अधिसूचना जारी, मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले, तीनों शहरों के व्यापक विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी

- मुख्यमंत्री ने कहा सिखों के पांच तख्त साहिबान में से तीन पंजाब में हैं
- बोले, ये शहर रूहानियत का केंद्र नहीं, हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़

पंजाब सरकार ने सिखों के लिए धार्मिक महत्व वाले तीन शहरों अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब व तलवंडी साबो की वाल्ड सिटी को पवित्र शहर का दर्जा देने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। यह जानकारी रविवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक वीडियो संदेश जारी कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। अब यहां मांस, शराब, तंबाकू पदार्थ और किसी भी नशीले पदार्थ की बिक्री पर प्रतिबंध होगा और यहां पर अब सख्त नियम लागू होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, सिखों के पांच तख्त साहिबानों में से तीन पंजाब में हैं। अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब, श्री आनंदपुर साहिब में तख्त श्री केसगढ़ साहिब और तलवंडी साबो में तख्त श्री दमदमा साहिब स्थित हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को मनाने के लिए आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के मौके पर श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती से इन तीनों शहरों की वाल्ड सिटी को पवित्र शहर घोषित किया गया था।

उन्होंने कहा, मैं आश्वासन देता हूं कि इन शहरों के समग्र और उचित विकास को सुनिश्चित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये शहर केवल रूहानियत का केंद्र नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का शानदार प्रतीक भी हैं।

प्रदेश सरकार इन पवित्र शहरों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करेगी ताकि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं और संगत को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

क्या है वाल्ड सिटी

वाल्ड सिटी वह क्षेत्र है जोकि अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो का पुराना अर्थात अंदरूनी इलाका है। समय के साथ-साथ शहरों का दायरा बढ़ता गया लेकिन यह पाबंदियां केवल अंदरूनी शहर में ही लागू होंगी।

श्री आनंदपुर साहिब। फाइल

****

Dainik Jagaran Page No-3

बिजली संशोधन विधेयक पर फिर से संशय

2014 से ही लटका हुआ है विधेयक, दो बार सरकार इसे संसद में पेश कर चुकी है

तीन बार अलग से इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया, दो बार संसदीय समिति ने किया विचार

जयप्रकाश रंजन • जागरण

- बिजली मंत्री की अध्यक्षता में गत दिनों सलाहकार समिति की बैठक में विधेयक पर विस्तार से हुई चर्चा
- राज्यों की आपत्ति, आम जनता और किसानों को सब्सिडी देने का अधिकार छिन जाएगा

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली : देश के बिजली क्षेत्र में, खास तौर पर बिजली वितरण व्यवस्था में बदलाव करने, बिजली क्षेत्र में क्रास-सब्सिडी की व्यवस्था (एक खास वर्ग से ज्यादा वसूलना, कुछ अन्य वर्ग को सस्ती या फ्री बिजली देना) को खत्म करने, देश में सही मायने में पूरी तरह से एक बाजार आधारित बिजली कारोबारी व्यवस्था बनाना, बिजली शुल्क तय करने में किसी भी तरह की राजनीतिकरण को रोकने की बात करने के उद्देश्य से बिजली कानून 2003 में व्यापक संशोधन करने वाले इस विधेयक को लेकर असमंजस बरकरार है। केंद्र सरकार 2014 से अभी तक दो बार संसद में इसे पेश कर चुकी है। दो बार इस विधेयक को संसदीय समितियों को भेजा गया और तीन बार अलग से इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया। फिर भी कभी राज्यों के विरोध की वजह से तो कभी कुछ अन्य वजह से सरकार इस पर दो टूक कदम नहीं उठा पाई। हद तो यह है कि केंद्र सरकार ने कुछ ही हफ्तों के भीतर सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट आफ न्यूक्लियर एनर्जी फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया (शांति) बिल, 2025 को अंतिम रूप भी दे दिया और उसे पारित भी करा लिया। लेकिन बिजली संशोधन विधेयक 2025 पर मशविरा का दौर चलता ही जा रहा है। शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद तो इस विधेयक को अब अगले वर्ष बिजली संशोधन विधेयक, 2026 के नाम से ही पेश किया जा सकेगा।

पिछले शुक्रवार को केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बिजली मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में उक्त विधेयक को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा को लेकर जो बातें सामने आई हैं, उससे यह लगता है कि प्रस्तावित विधेयक के जिन प्रस्तावों को लेकर राज्यों का विरोध था, वह अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। राज्य सरकारों में शुरू से ही इस विधेयक को लेकर एक आपत्ति है कि यह उन्हें आम जनता और किसानों को सब्सिडी देने के अधिकार से वंचित कर देगा। 2014 में जब पहली बार यह विधेयक तत्कालीन बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया था, तब 12 राज्य सरकारों ने इसी आधार पर इसका विरोध किया था। तब विरोध करने वाले अधिकांश राज्य गैर भाजपाई थे। इनमें से कई राज्यों में अब भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन राज्यों का विरोध बहुत कम नहीं हुआ है। इस विरोध के पीछे राजनीति भी है। केंद्र सरकार के स्तर पर बार-बार यह सफाई दी गई है कि राज्यों की तरफ से बिजली सब्सिडी देने के अधिकार पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि में श्रम संगठन इसे शुरू से ही निजीकरण का रोडमैप बता रहे हैं। केरल, पंजाब व बंगाल इसे संघीय ढांचे के खिलाफ भी बताया जा रहा है। 18 दिसंबर की बैठक में बिजली मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें घरेलू व कृषि उपभोक्ताओं जैसे प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ता समूहों को सब्सिडी देना जारी रख सकती हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वित्तीय अनुशासन और उपभोक्ता कल्याण साथ-साथ चले।

केंद्र द्वारा जारी सूचना के अनुसार, उन्होंने स्पष्ट किया कि निजीकरण, लागत में वृद्धि या कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंकाओं का कोई आधार नहीं है। उपभोक्ताओं या कर्मचारियों के किसी भी वर्ग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त नियामकीय और नीतिगत उपाय किए जाएंगे।

केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल की तरफ से इस बैठक को बिजली संशोधन विधेयक पर राज्यों की सहमति हासिल करने की अंतिम कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस आश्वासन का कम से कम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल जैसे गैर भाजपाई सरकारों पर कोई फर्क पड़ने की संभावना नहीं है। अप्रैल-मई 2026 में बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों को देखते हुए अब अगले वर्ष मानसून सत्र में ही इसे पेश किए जाने की संभावना है।

Dainik Jagaran Page No-3

राष्ट्रपति की मंजूरी: 'वीबी-जी राम जी' बिल बना कानून, मनरेगा की ली जगह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कानून में पंचायतों को योजना बनाने की शक्ति, 125 दिनों का रोजगार मिलेगा
- केंद्र ने की अधिसूचना जारी, विपक्ष के विरोध के बीच पारित कराया था बिल

द्रौपदी मुर्मु। फाइल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रविवार को विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक ('वीबी जी राम जी विधेयक, 2025') को अपनी स्वीकृति दे दी, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का स्थान लेता है और ग्रामीण श्रमिकों के लिए 125 दिनों के रोजगार का प्रविधान करता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ यह विधेयक अब कानून बन गया है और इस संबंध में एक अधिसूचना भारत के गजट में प्रकाशित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक बयान में इसे भारत के ग्रामीण रोजगार और विकास ढांचे में एक निर्णायक सुधार बताया है।

भारत को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लक्ष्य में गांवों व ग्रामीणों के विकास को बहुत अहम मानकर चल रही मोदी सरकार की ग्रामीण रोजगार नीति आखिरकार बड़े बदलावों के साथ धरातल पर उतरने जा रही है। गत दिनों शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के भारी विरोध के बीच राजग सरकार के लाए गए 'वीबी जी राम जी अधिनियम-2025' में कई अहम बदलाव किए गए हैं। इसके तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी को मनरेगा में तय सौ दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। बुआई-कटाई के सीजन में खेती से संबंधित गतिविधियों के लिए कृषि श्रम की उपलब्धता आसान करने को यह अधिनियम राज्यों को एक वित्त वर्ष में कुल 60 दिनों की विराम अवधि अधिसूचित करने का अधिकार देगा। इस अधिनियम में मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या कार्य की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर किए जाने की अनिवार्यता है। देरी होने पर विलंब मुआवजा दिया जाएगा। इस कानून के तहत कराए जाने वाले कार्यों को भी सरकार ने तय कर दिया है। इसके तहत चार प्राथमिक क्षेत्र हैं, जिसमें जल सुरक्षा एवं जल से संबंधित कार्य, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से संबंधित अवसंरचना और प्रतिकूल मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करने वाले काम। इससे धरातल पर होने वाला काम दिखाई देगा और उसका लाभ भी ग्रामीण विकास में मिलेगा। कार्य तय करने का अधिकार पंचायतों को दिया गया है। ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों की सहमति से गांव की आवश्यकता के आधार पर कार्य निर्धारण होगा।

प्रेट्र के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो संदेश में नई योजना को मनरेगा से एक कदम आगे बताते हुए आरोप लगाया कि इसके बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। कहा, वीबी-जी राम जी योजना के लिए 1,51,282 करोड़ रुपये आबंटित किए जाएंगे ताकि ग्रामीण रोजगार के लिए पर्याप्त धन रहे।

संसदीय परंपराओं को दरकिनार कर प्रगति को पलटा: कांग्रेस

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस ने रविवार को मोदी सरकार पर "मनरेगा जैसे ऐतिहासिक कानून का अपमान" करने का आरोप लगाया और कहा कि दो दशकों की प्रगति को "परामर्श के बिना" और सभी संसदीय (पार्लियामेंटरी) परंपराओं और प्रक्रियाओं को दरकिनार करके पलटा गया है। विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा कि काम के अधिकार पर यह "गंभीर हमला" 27 दिसंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चर्चा का विषय बनेगा, जहां पार्टी भविष्य की कार्रवाई की रूपरेखा तय करेगी। ज्ञात हो, गुरुवार को संसद ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक पारित किया, जो 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को मंजूरी दिए जाने के साथ ही यह कानून बन गया है।

कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने 2012 में यूपीए सरकार द्वारा जारी ग्रामीण रोजगार योजना की समीक्षा दस्तावेज को एक्स पर साझा किया, ताकि इसके उपलब्धियों को रेखांकित किया जा सके। कहा,14 जुलाई, 2012 को तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी मनरेगा समीक्षा का विमोचन किया था। कांग्रेस नेता ने मनरेगा समीक्षा दस्तावेज की प्रस्तावना का स्क्रीनशाट भी साझा किया, जिसे उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रभारी रहते हुए जारी किया था।

कांग्रेस के महासचिव और संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मनरेगा को अधिकार से एक कृपा में बदलकर प्रभावी रूप से "विघटित" कर दिया है। उन्होंने कहा, "मनरेगा काम का कानूनी अधिकार था, न कि कल्याणकारी सहायता।" कांग्रेस पार्टी ने रविवार को देशभर के सभी जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन आयोजित किया है। काम के अधिकार पर यह गंभीर हमला 27 दिसंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी चर्चा का विषय बनेगा, जहां पार्टी विचार-विमर्श करेगी और भविष्य की कार्रवाई तय करेगी। इसके बाद 28 दिसंबर कांग्रेस कार्यकर्ता भारत के मंडलों और पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

- जयराम रमेश ने मनरेगा के अपमान करने का आरोप लगाया
- 27 को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में इस पर चर्चा होगी

जयराम रमेश। फाइल

केसी वेणुगोपाल। फाइल

Dainik Jagaran Page No-3

नहीं रही अरावली तो कैसे बचेगा एनसीआर

कैसे बचे अरावली

आदित्य राज • जागरण

- केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की नई परिभाषा से गंभीर संकट में अरावली की पहाड़ियां
- 100 मीटर ऊंचाई को पैमाना माना गया तो 90% तक खत्म हो जाएगी यह पर्वत श्रृंखला

अरावली क्षेत्र में विचरण करते वन्यजीव • फाइल

गुरुग्राम: दिल्ली से गुजरात तक फैली अरावली पर्वत श्रृंखला न सिर्फ देश के पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के लिए जरूरी है, बल्कि एनसीआर के लिए यह ढाल की तरह है। लेकिन, पर्वत की ऊंचाई तय करने की नई परिभाषा इसके अस्तित्व पर संकट खड़ा कर सकती है।

नई परिभाषा के अनुसार स्थानीय धरातल से 100 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली की पहाड़ियां मानी जाएंगी। ऊंचाई का मापदंड समुद्र तल से तय होता है। गुरुग्राम एवं दिल्ली के धरातल की ऊंचाई समुद्र तल से 240 से 260 मीटर के आसपास है, जबकि क्षेत्र में फैली अरावली की अधिकतर पहाड़ियों की ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है। ऐसे में नई परिभाषा के अनुसार, अरावली की ज्यादातर पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम हो जाती है। इससे अरावली का 95 प्रतिशत तक क्षेत्र इसके दायरे से बाहर हो जाएगा। अरावली की बर्बादी का मतलब है पूरे एनसीआर में जीवन पर गंभीर संकट। ये पहाड़ियां ही राजस्थान से चलने वाली धूल भरी हवाओं को काफी हद तक रोकती हैं। यह धूल एनसीआर के प्रदूषण में अहम कारक भी है। यही नहीं, भूकंप के हिसाब से पूरा एनसीआर संवेदनशील जोन-चार के दायरे में आता है।

अरावली की वजह से ही यहां भूकंप का अधिक असर नहीं होता। ऐसे में अरावली की पहाड़ियों को बचाना जीवन बचाना है। इसे ध्यान में रखकर दैनिक जागरण ने 'कैसे बचे अरावली' नाम से समाचारीय श्रृंखला शुरू की है। विभिन्न कड़ियों में यह बताया जाएगा कि अरावली की बर्बादी से पूरे एनसीआर क्षेत्र में जीवन कैसे संकट में पड़ जाएगा।

खनन की वजह से इस तरह जगह-जगह है अरावली का सीना छलनी • जागरण

अरावली क्यों है एनसीआर के लिए महत्वपूर्ण

एनसीआर में अरावली की पहाड़ियां न सिर्फ इस क्षेत्र, बल्कि उत्तर भारत के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। ये थार रेगिस्तान के एनसीआर की ओर विस्तार को रोकती हैं, रेगिस्तान से आने वाली धूल व गर्म हवाओं को एनसीआर में पहुंचने से रोकती हैं। इनके कारण क्षेत्र में हरियाली, वानिकी और पर्यावरणीय संतुलन है। ये भूजल संग्रहण का बड़ा स्रोत भी हैं हैं। खनन व भूमाफिया के सक्रियता के बीच अब अरावली पहाड़ियों को क्षति पहुंचाने वाला अन्य कोई भी कदम एनसीआर के लिए और मुश्किलें पैदा करने वाला होगा। बढ़ते रेगिस्तान, तापमान, वायु प्रदूषण व जल संकट से एनसीआर में लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा।

सात जनवरी को होगी मामले में सुनवाई

अरावली की नई परिभाषा के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरणविद् व सेवानिवृत्त वन संरक्षक डा. आरपी बालवान द्वारा दायर याचिका पर सात जनवरी को सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ ही दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एवं गुजरात सरकार को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने को कहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि वे अरावली को बचाने के लिए अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे। इसे बचाने के लिए आम लोगों को भी आगे आना चाहिए।

"केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई अरावली की नई परिभाषा से एनसीआर में लोगों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला है न कि एक पहाड़, ऐसे में इसकी परिभाषा ऊंचाई से तय करना गलत है। यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह जितना ऊपर है उससे कहीं अधिक नीचे है। भूमाफिया एवं खनन माफिया के इशारे पर नई परिभाषा बनाई गई है। परिभाषा बनाने वालों को इस बात का अहसास होना चाहिए कि इसके बिना यहां सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अरावली के रहने पर धूल भरी हवाएं काफी आ रही हैं, न रहने पर क्या होगा। राजस्थान का मरुस्थल दिल्ली तक फैल जाएगा। एक तरफ अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ अरावली को ही खत्म करने की तैयारी है।

-**डा. आरपी बालवान,** पर्यावरणविद् व सेवानिवृत्त वन संरक्षक

Dainik Jagaran Page No-2

अंतरिक्ष शिक्षा को नई उड़ान

देश के सात उच्च शिक्षण संस्थानों में स्थापित होंगी अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं

अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के दबदबे को बढ़ाने के लिए तैयार होगा इकोसिस्टम, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना को पंख दे रहा इन-स्पेस, छात्रों को मिलेगा व्यावहारिक प्रशिक्षण, निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को मिलेगा कुशल मानव संसाधन

नई दिल्ली, प्रेट्र: 2047 तक अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत पकड़ बनाने के लक्ष्य के साथ भारत ने अपने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ा दिए हैं। इसी कड़ी में देशभर के चुनिंदा उच्च शिक्षण संस्थानों में अत्याधुनिक 'अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं' स्थापित की जाएंगी, ताकि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुरूप कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार किया जा सके।

इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (आइएन-एसपीएसीई या इन-स्पेस) ने सात अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य कक्षा आधारित पढ़ाई को प्रयोगशाला के व्यावहारिक अनुभव से जोड़ना है। इन प्रयोगशालाओं के जरिये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को न सिर्फ हाथों-हाथ प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि उन्हें वास्तविक अंतरिक्ष परियोजनाओं की कार्यप्रणाली से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा। इन-स्पेस ने योजना लागू करने के लिए रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) जारी कर दी है। इसके तहत चयनित शैक्षणिक संस्थानों में आधुनिक प्रयोगशालाओं स्थापित की जाएगी, जहां छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में हाथों-हाथ सीखने का अवसर मिलेगा।

2033 तक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 44 अरब डालर होने का अनुमान

प्रतीकात्मक

उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच बढ़ेगा सहयोग : इन-स्पेस के प्रमोशन निदेशालय के निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि यह पहल उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच सार्थक सहयोग को बढ़ावा देगी और भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाने के दीर्घकालिक लक्ष्य को समर्थन देगी। कहा, साझा प्रयोगशालाओं के माध्यम से एप्लायड रिसर्च, शुरुआती नवाचार और उद्योग की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा।

लैब के लिए अलग-अलग हिस्सों से चुने जाएंगे संस्थान : योजना के तहत देश के सात अलग-अलग क्षेत्रों से चरणबद्ध तरीके से अधिकतम सात संस्थानों का चयन किया जाएगा। इन-स्पेस कुल परियोजना लागत का 75 प्रतिशत तक, अधिकतम पांच करोड़ रुपये प्रति संस्थान को वित्तीय मदद देगा। आवेदन के लिए संस्थान का कम से कम पांच वर्ष पुराना होना, एनआइआरएफ रैंकिंग में 200 के भीतर होना और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित पाठ्यक्रम संचालित करना अनिवार्य होगा। चयनित संस्थानों से उद्योग के साथ तकनीकी विकास परियोजनाओं में सहयोग को भी प्रोत्साहित करने की अपेक्षा की जाएगी।

अमेरिकी सेटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाएगा इसरो का 'बाहुबली'

चेन्नई: अंतरिक्ष क्षेत्र में कई कीर्तिमान रच चुका भारत 24 दिसंबर को एलवीएम-3 एम6 मिशन के तहत अमेरिकी सेटेलाइट ब्ल्यूबर्ड- ब्लाक-2 को अंतरिक्ष में ले जाएगा। इसरो का 'बाहुबली' राकेट एलवीएम-3 इस सेटेलाइट को कक्षा में पहुंचाएगा। इस मिशन में अगली पीढ़ी के संचार उपग्रह की तैनाती होगी, जिसे स्मार्टफोनों में उच्च गति के सेलुलर ब्राडबैंड पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। (पेज-6)

अंतरिक्ष से मिसाइल ट्रैकिंग करेगा स्वदेशी स्टार्टअप 'दिगंतर' पेज>>6

****

Dainik Jagaran Page No-1

भारत लगातार दूसरी बार फाइनल हारा, पाक ने जीता एशिया कप

अंडर-19 क्रिकेट

दुबई, एजेंसी। भारतीय जूनियर टीम लगातार दूसरे साल अंडर-19 वनडे एशिया कप के खिताब से चूक गई। पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहने वाली आयुष म्हात्रे की टीम फाइनल की बाधा पार नहीं कर पाई। भारत को खिताबी मुकाबले में रविवार को पाकिस्तान के हाथों 191 रन से हार मिली।

इस जीत के साथ पाकिस्तान ने 11 साल में पहली जबकि कुल दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा किया। इससे पहले 2012 में मैच टाई होने पर भारत के साथ संयुक्त विजेता रहा था।

पाकिस्तान ने समीर मिन्हास (172) के शतक से आठ विकेट पर 347 रन का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में भारतीय टीम मात्र 26.2 ओवर में 156 रन पर लुढ़क गई।

दसवें नंबर के बल्लेबाज दीपेश देवेंद्रन (36) और वैभव सूर्यवंशी (26) ही 20 का आंकड़ा पार कर सके। अली राजा ने म्हात्रे को चौथे ओवर में आउट कर जो झटका दिया उससे टीम अंत तक उबर नहीं पाई। पाक की ओर से अली ने चार विकेट चटकाए। इससे पहले समीर ने अपना दूसरा शतक जड़ा। उस्मान ने 35, हमद हुसैन ने 56 और फरहान ने 19 रन बनाए। दीपेश ने तीन विकेट झटके।

दुबई में रविवार को फाइनल में शतकीय पारी खेलने के बाद जश्न मनाते पाकिस्तान के ओपनर समीर मिन्हास। • एजेंसी

276 सर्वाधिक रन भारत की ओर से टूर्नामेंट में अभिज्ञान ने 138 की औसत से बनाए

471 रन के साथ टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर रहे पाकिस्तान के ओपनर समीर मिन्हास

नहीं चले वैभव

धमाकेदार शतक के साथ आगाज करने वाले 14 साल के वैभव फाइनल में बेदम रहे। उन्होंने छक्के से शुरुआत की पर क्रीज पर टिक नहीं पाए। उनका आउट होना भारत के लिए सबसे बड़ा झटका रहा।

कप्तान म्हात्रे का फ्लॉप शो

कप्तान म्हात्रे टूर्नामेंट में एक अर्धशतक तक नहीं जड़ पाए। वह पांच मैचों में 58 गेंद खेलकर 13 की औसत से मात्र 65 रन बना पाए। फाइनल में वह दो रन बनाकर चलते बने।

दीपेश ने लुटा दिए 83 रन

तेज गेंदबाज दीपेश ने तीन विकेट तो झटके पर 83 रन भी लुटा दिए। यह युवा वनडे में एक पारी में लुटाए गए सर्वाधिक रन है। उन्होंने अम्बरीश का 80 रन का रिकॉर्ड तोड़ा।

टीम ने नकवी से पदक नहीं लिए

दुबई। भारतीय खिलाड़ियों ने एक बार फिर पाक क्रिकेट प्रमुख मोहसिन नकवी की फजीहत की। नकवी विजेता ट्रॉफी देने मंच पर आए। उन्हें टीम को उपविजेता की ट्रॉफी और पदक देने थे, मगर भारतीय खिलाड़ी मंच तक नहीं गए। उन्होंने आईसीसी एसोसिएट सदस्य देशों के डायरेक्टर मुबश्शिर उस्मानी से पदक लिए। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मैच के बाद एक-दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाए।

Hindustan Page No-14

आत्मसम्मान की रोशनी

महिमा सामंत

जीवन के हर मोड़ पर व्यक्ति अनेक भूमिकाएं निभाता है- पुत्र, मित्र, शिक्षक, कर्मचारी, नागरिक। इन सभी पहचानों के बीच एक पहचान ऐसी है जो सबसे स्थायी है- स्वयं की। आत्मसम्मान उसी पहचान का मूल है। यह वह मौन शक्ति है जो व्यक्ति को परिस्थितियों के आगे झुकने नहीं देती, बल्कि उन्हें आकार देने की प्रेरणा देती है। आत्मसम्मान वह अदृश्य दीपक है, जो भीतर जलता है और अंधकार के समय दिशा दिखाता है। इसक अर्थ है स्वयं को स्वीकारना, अपनी क्षमताओं को पहचानना और जीवन के प्रति गरिमा का भाव बनाए रखना। यह अहंकार नहीं, बल्कि आत्म-स्वीकार की परिपक्वता है। अहंकार दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करता है, जबकि आत्मसम्मान स्वयं को गरिमा से ऊंचा उठाता है। यह उस व्यक्ति की पहचान है जो कहता है कि 'मैं जैसा हूं, वैसा ही पर्याप्त हूं।'

कभी-कभी जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं, जो बार-बार हमें चोट पहुंचाते हैं, अपमानित करते हैं, और फिर एक साधारण 'सारी' या 'माफी' कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं। वे वही गलती दोहराते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम हमेशा की तरह माफ करते रहेंगे। पर हर 'सारी' रिश्ते को नहीं जोड़ती। क्षमा तभी अर्थपूर्ण होती है, जब सामने वाला अपनी गलती की गहराई सच में समझे। आत्मसम्मान का अर्थ कठोर होना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि क्षमा वहीं तक उचित है, जहां हमारी गरिमा सुरक्षित रहे। जब किसी की गलती इतनी गहरी हो कि उसे भूलना खुद के साथ अन्याय लगे, तब दूरी बनाना गुस्सा नहीं, अपनी मानसिक शांति और स्वाभिमान की रक्षा करना होता है। दूसरों को माफ करना अच्छा है, पर खुद को भूल जाना कभी नहीं। इसी तरह, जब कार्यस्थल पर हमारी मेहनत को बार-बार नजरअंदाज किया जाता है, हमारी योग्यता को महत्त्व नहीं दिया जाता या हमारा योगदान किसी और के नाम कर दिया जाता है, तो चुप रहकर सब लंबे समय तक सहना विनम्रता नहीं, बल्कि अपने मूल्य को कम आंकना है। वहां अपनी काबिलियत के लिए शांत, पर दृढ़ आवाज उठाना ही सच का पक्ष और स्वाभिमान की रक्षा बन जाता है।

रिश्तों में भी कई बार हम अनजाने में ऐसी आदत पाल लेते हैं कि हर बहस के बाद 'माफी' हम ही बोलते हैं, चाहे गलती सामने वाले की हो। हम सोचते हैं कि इससे रिश्ता बचेगा, पर धीरे-धीरे हम खुद को खोने लगते हैं। इस चक्र को रोकना, अपनी बात, अपने दर्द और सम्मान को तवज्जो देना दरअसल अपनी कद्र करना है। कुछ स्थितियों में गलत व्यवहार इतना गहरा होता है कि शब्द बेअसर हो जाते हैं। वहां चुप्पी ही सबसे मजबूत जवाब बन जाती है।

जब कोई व्यक्ति हमें सिर्फ तब याद करे, जब उसे हमारी जरूरत हो, काम निकालना हो, सहानुभूति चाहिए हो, या अकेलापन बांटना हो, पर हमारी जरूरत के समय वह हमेशा गायब मिले, तो ऐसे रिश्तों से दूरी बनाना भी स्वाभिमान का ही हिस्सा है। खुद को हर समय उपलब्ध न कराना, अपनी ऊर्जा और भावनाओं की रक्षा करना, और यह समझना कि हर कोई हमारे दिल तक पहुंचने का अधिकार नहीं रखता, यही आत्मसम्मान की असली शुरुआत है। सच तो यही है कि स्वाभिमान वहीं बचता है, जहां हम खुद को खोने से पहले रुकना और अपनी गरिमा को प्राथमिकता देना सीखते हैं।

आत्मसम्मान केवल दूसरों से व्यवहार का विषय नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति दृष्टिकोण का विषय है। जब कोई व्यक्ति गलती करता है और बिना बहाने के 'हां, मुझसे भूल हुई' कहने की हिम्मत रखता है, वह आत्मसम्मानित होता है। जब कोई अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, चाहे सामने लाभ ही क्यों न हो, वह आत्मसम्मान जी रहा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मसम्मान केवल बड़े निर्णयों में दिखता है, पर सच्चाई यह है कि यह हमारी रोजमर्रा की आदतों में बसता है। जब कोई विद्यार्थी नकल से इनकार करता है, कोई महिला अपने अधिकार के लिए बोलती है, या कोई व्यक्ति अपमानित होकर भी शांत और संयमित रहता है, तो ये सभी आत्मसम्मान के जीवंत उदाहरण हैं।

आज सोशल मीडिया और तुलना की दुनिया में लोग अपनी कीमत 'लाइक' और 'फालोअर्स' से मापने लगे हैं। पर आत्मसम्मान हमें सिखाता है कि पहचान भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है, वही दूसरों को प्रेरणा दे सकता है। आत्मसम्मान हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। यह चिंता, असुरक्षा और आत्मसंदेह से बचाता है। जब हम खुद को स्वीकारते हैं, तब हम दुनिया की अपेक्षाओं में उलझते नहीं, बल्कि अपने जीवन की दिशा खुद तय करते हैं। यह एक ऐसा मौन कवच है, जो हमें हर असमानता, उपेक्षा और अपमान से बचाता है।

जीवन का सबसे बड़ा संतोष यह नहीं कि दुनिया हमें कितना सम्मान देती है, बल्कि यह है कि हम स्वयं को कितना सम्मान देते हैं। आत्मसम्मान कोई पदक नहीं है, जिसे कोई और दे। यह आत्म-निर्णय है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपनी गरिमा से समझौता नहीं करूंगा। कभी-कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है, जहां चुप रहना आसान होता है, पर स्वयं का सम्मान बचाना कठिन। ऐसे क्षणों में याद रखना चाहिए कि दुनिया की नजरों में हार जाना भी स्वीकार्य है, अगर अपने भीतर हम विजेता हैं। आत्मसम्मान वही रोशनी है जो हमें हर अंधेरे से पार ले जाती है। जब हम खुद का सम्मान करना सीख लेते हैं, तब हमें किसी और से स्वीकृति मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो अपने भीतर की गरिमा को पहचान लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन जीता है।

दुनिया मेरे आगे

हमारे जीवन का सबसे बड़ा संतोष यह नहीं कि दुनिया हमें कितना सम्मान देती है, बल्कि यह है कि हम स्वयं को कितना सम्मान देते हैं। आत्म-सम्मान कोई पदक नहीं है, जिसे कोई और दे। यह आत्म-निर्णय है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपनी गरिमा से समझौता नहीं करूंगा।

नई योजना और रोजगार की चुनौतियां

नए सर्वेक्षणों के मुताबिक, इस कृषि प्रधान देश में ग्रामीण बेरोजगारी की दर बढ़ने लगी है। ग्रामीण इलाकों में आज भी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। क्या मनरेगा का बदला रूप 'वीबी-जी राम जी' इस चुनौती का मुकाबला कर पाएगा।

सुरेश सेठ

भारत तरक्की कर रहा है, आंकड़ों से अर्शशास्त्री यही बताते हैं। निस्संदेह भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में देश तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा और 2047 में जब आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तब हम पूरी तरह से एक विकसित राष्ट्र होंगे। उस समय हर आदमी यथोचित रोजगार के साथ अच्छा भोजन करेगा, अच्छा पहनेगा और खुशहाली के शिखर पर होगा। यह है सपना। ऐसा अगर लोग स्वाधीनता का अमृत महोत्सव के बाद भी सोचते हैं, तो कारणों की तलाश करनी पड़ेगी। पिछले दिनों कहा गया कि हम देश से बेरोजगारी मिटा देंगे। बेरोजगारी की भूख अनुकंपा के सस्ते राशन से मिटा दी जाएगी। मगर युवा पीढ़ी जो इस देश की आधी आबादी है, वह काम चाहती है। यह कड़वी सच्चाई है कि बड़ी संख्या में युवा आज भी बेरोजगार हैं। नए सर्वेक्षणों ने बताया है कि इस कृषि प्रधान देश में ग्रामीण बेरोजगारी की दर बढ़ने लगी है। ग्रामीण इलाकों में आज भी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। क्या मनरेगा का बदला रूप 'वीबी-जी राम जी' इस चुनौती का मुकाबला कर पाएगा, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि गांवों में योजना का नया कलेवर नहीं, काम चाहिए।

अब जरूरत है कि देश में नागरिकों को काम के उचित अवसर मिलें। यूपीए सरकार के समय सबसे अच्छी योजना मनरेगा को ही बताया जाता था। यह फरवरी 2006 में लागू हुई थी। इसमें आवेदन करने पर पंद्रह दिन के अंदर रोजगार देना अनिवार्य होता था। आंकड़े बताते हैं कि इस पर अब तक 11.74 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। वर्ष 2014 से राजग सरकार के कार्यकाल में भी इस पर 7.8 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। हालांकि इसमें केवल सौ दिन का काम दिया जाता है। कई बार तो मजदूरों को औसत पचास दिन ही काम मिला। फिर भी मनरेगा वर्ष 2014 से अब तक आठ करोड़ लोगों को ही रोजगार दे पाई।

अब केंद्र सरकार ने संसद में नया ग्रामीण रोजगार विधेयक पारित किया है। ग्रामीणों को रोजगार के लिए 20 साल के बाद योजना को एक नया कलेवर दिया गया है। इसकी शुरुआत नाम बदलने से हुई। इस योजना का नया नाम है- विकसित भारत-जी राम जी। जबकि इससे पहले इसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कहा जाता था। कुल जमा ये कि नई योजना ने रूप बदला है। पहले सौ दिन काम मिलता था, लेकिन अब 125 दिन काम मिलेगा, लेकिन दिहाड़ी वही रहेगी। पहले इस योजना पर सौ फीसद पैसा केंद्र सरकार खर्च करती थी। अब इसमें 60 फीसद योगदान केंद्र देगा। जबकि 40 फीसद राज्य सरकारें देंगी। पहले इस योजना में आवेदन करने पर 15 दिन के भीतर काम मिलता था। मगर अब काम न मिलने पर राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। मनरेगा ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए था। फिलहाल 'वीबी-जी राम जी' को विकसित भारत का हिस्सा बना कर देखा जा रहा है।

नई योजना की डिजिटल निगरानी होगी। ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषदें बनेंगी। संचालन समितियां बनेंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर बनने वाली योजनाओं को 'पीएम-विकास गतिशक्ति' से जोड़ देंगे। अब सवाल

है कि इस परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी? संसद में विधेयक पारित भी हो गया है। इससे पहले इस पर सत्तापक्ष और विपक्ष की जम कर बहस हुई। सत्तापक्ष का कहना था कि मनरेगा दिशाहीन था और इसमें ऐसा था कि पहले गड्ढे खोदो, फिर उन्हें भर दो। मुख्य उद्देश्य था गरीब परिवार के

> विपक्ष के अपने तर्क हैं कि क्या ऐसे ही प्रावधान मनरेगा में नहीं किए जा सकते थे! क्या उसे निश्चित उद्देश्यों के साथ लक्ष्यबद्ध नहीं किया जा सकता था? फिर जरूरी तो यह था कि महंगाई की दर को देखते हुए कार्यबल के पारिश्रमिक में वृद्धि कर दी जाती। वृद्धि तो की नहीं, केवल काम के 25 दिन बढ़ा दिए। राज्य सरकारें तो पहले ही अपने खाली खजाने का रोना रो रही हैं। उनका यह कहना है कि ग्रामीण विकास कोष से लेकर जीएसटी तक में से उन्हें उनका उचित भुगतान नहीं मिलता। अब उन पर इस योजना के योगदान का 40 फीसद भार भी डाल दिया गया है।

एक सदस्य को सौ दिन काम देकर मेहनताना देना। अब यह नई योजना दिशाहीन नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार का मत है कि गांवों में परिवर्तन आ गया है। भुखमरी कम हो गई है, ग्रामीण बेरोजगारी इतनी बड़ी चुनौती नहीं रही। मगर सच से कैसे इनकार किया जा सकता है? चुनौती तो अब भी है! सरकार का यह भी कहना है कि ग्रामीण भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना बदल रही है। वहां डिजिटल भुगतान पहुंच गया है। बैंक पहुंच गए हैं। बेहतर संपर्क है, लेकिन मनरेगा में फर्जीवाड़ा हो रहा था। योजना की राशि का दुरुपयोग हो रहा था। यह भी कहा जा रहा है कि पंजाब जैसे राज्यों में इतनी कम दिहाड़ी पर मजदूर काम करने के लिए राजी नहीं। इसलिए वहां फर्जी आंकड़ों से भुगतान हो रहे हैं।

विशेषज्ञ कहते हैं कि वर्ष 2024-25 में इस योजना में 194 करोड़ रुपए का घपला हुआ और केवल 7.6 फीसद ग्रामीण परिवार ही सौ दिन का रोजगार पा सके, लेकिन अब माहौल बदल जाएगा। फर्जीवाड़ा रुकेगा। अब यह चुस्त-दुरुस्त और नए कलेवर वाली योजना बनेगी, जिस पर बाकायदा काम होगा। श्रम बल को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा जाएगा। यह यथार्थवादी योजना होगी। जब गांवों में फसल बिजाई और फसल कटाई का भरपूर आंशिक योगदान मिलने की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो यह योजना समांतर रोजगार देना स्थगित कर देगी। बाद में लक्ष्यबद्ध तरीके से कार्यबल का इस्तेमाल किया जाएगा जो ग्रामीण जीवन का कायाकल्प कर देगा।

दूसरी ओर विपक्ष के अपने तर्क हैं कि क्या यही नया कलेवर मनरेगा को नहीं दिया जा सकता था? क्या उसे निश्चित उद्देश्यों के साथ लक्ष्यबद्ध नहीं किया जा सकता था। फिर जरूरी तो यह था कि महंगाई की दर देखते हुए कार्यबल के पारिश्रमिक में वृद्धि कर दी जाती। वृद्धि तो की नहीं, केवल काम के 25 दिन बढ़ा दिए। राज्य सरकारें तो पहले ही अपने खाली खजाने का रोना रो रही हैं। उनका यह कहना है कि ग्रामीण विकास कोष से लेकर जीएसटी तक में से उन्हें उनका उचित भुगतान नहीं मिलता। मुआवजा नहीं मिलता। अब उन पर इस योजना के योगदान का 40 फीसद भार भी डाल दिया गया है। राज्य सरकारें तो अधिक आर्थिक सहायता की उम्मीद केंद्र से कर रही थीं, लेकिन यहां एक और दायित्व उन पर आ गया कि अगर ग्रामीण विकास को तेजी देनी है, तो आगे बढ़ो और केंद्र सरकार के साथ योगदान करो। यह भी कहा गया कि पंजाब ही नहीं, बल्कि बंगाल में भी इस कोष का भारी दुरुपयोग हुआ। इसलिए नया विधेयक लाया गया।

यह योजना क्या काम करेगी, इसे स्पष्ट किया गया है। यह मूलभूत बुनियादी ढांचा बनाएगी। आजीविका के लिए पूंजी का निर्माण करेगी और प्रदूषण से निपटने का कार्य करेगी। यह निराशाजनक है कि इस पर गंभीर चर्चा नहीं हुई। इसका नाम बदलने पर ही बहस होती रही। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है! मगर अब तो लगता है कि नाम में ही सब कुछ रखा है। सच तो यही है कि साम, दाम, दंड, भेद के साथ अपना नाम रोशन करने की यह जिद है। बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर इसे उत्सव की तरह मनाया जाता है। सत्ता की यह नई संस्कृति बनती जा रही है। ग्रामीण रोजगार संबंधी इस योजना को सार्थक बनाना है, तो उसके लिए आर्थिक आबंटन भी बढ़ना चाहिए। नई योजना में केंद्र सरकार ने आर्थिक आबंटन तो बढ़ाया नहीं, अलबत्ता राज्य सरकारों पर बोझ जरूर डाल दिया गया है। अब जिस प्रकार संवादहीनता गैर-भाजपा सरकारों और केंद्र के बीच चलती है, या जहां 'डबल इंजन' सरकारें नहीं हैं, वहां इस नई योजना का भविष्य क्या होगा, यह विचारणीय है। क्या योजना का नाम बदलने भर से सार्थकता साबित होगी?

Jansatta Page No-6

मुक्त व्यापार से खुलेगी प्रगति की राह

डा.जयंतीलाल भंडारी

अगले वर्ष होने वाले नए एफटीए भारत में निवेश-निर्यात बढ़ा कर उसे आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे

अनुकूल नीतियों से निर्यात में आ रही तेजी। फाइल

ट्रंप की टैरिफ चुनौतियों और वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर अनिश्चितताओं के बीच भारत के निर्यात में बढ़ोतरी का रुझान दिखा है। नवंबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच भारत का कुल निर्यात 64.05 अरब डालर से बढ़कर 73.99 अरब डालर हो गया। निर्यात में 15.52 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हुई है। इसके पीछे मुक्त व्यापार समझौतों यानी एफटीए की अहम भूमिका मानी जा रही है। नए वर्ष में अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों के साथ एफटीए के आकार लेने से भारत का निर्यात नई ऊंचाई पर होगा तथा भारत की व्यापार घाटे की चिंताएं कम होंगी। इसी पृष्ठभूमि में 19 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-न्यूजीलैंड एफटीए को मंजूरी दी है। दोनों देशों ने 14 साल पहले एफटीए पर बातचीत शुरू की थी। इस एफटीए से जहां वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार के साथ-साथ निवेश प्रवाह को बढ़ाने और आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मा, शिक्षा और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नए अवसर बनने की भी उम्मीद है।

इससे पहले ही 18 दिसंबर को ओमान के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस एफटीए को आधिकारिक तौर पर समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता (सीपा) कहा गया है। इस एफटीए के तहत भारत के 98 प्रतिशत निर्यात को ओमान में शून्य दर पर पहुंच मिलेगी। इसमें ओमान को होने वाले 99 प्रतिशत से अधिक निर्यात शामिल हैं। इससे भारत के कपड़ा, रत्न-आभूषण, दवाई, वाहन, कृषि उत्पाद और चमड़ा उद्योग को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। खासतौर से भारत से करीब 3.64 अरब डालर के निर्यात पर ओमान में फिलहाल लगने वाला पांच प्रतिशत शुल्क शून्य हो जाएगा। इसके बदले में भारत ने ओमान से आने वाले विभिन्न उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी सुनिश्चित की है। भारत ने अपनी करीब 78 प्रतिशत टैरिफ लाइन पर शुल्क में उदारता की पेशकश की है। ऐसे में मूल्य के लिहाज से ओमान से भारत में 95 प्रतिशत उत्पादों के शुल्क कम होंगे। इनमें खजूर, मार्बल और पेट्रोकेमिकल उत्पाद शामिल हैं। निश्चित रूप से इस एफटीए के तहत भारत के हित में कई अहम बातें हैं। भारत ने घरेलू हितों की रक्षा के लिए कुछ सख्त कदम भी उठाए हैं। पेशेवर आवाजाही पर भी एफटीए में भारत के हित हैं। पहली बार ओमान ने भारतीय पेशेवरों की आवाजाही पर व्यापक रियायतें दी हैं। 'इंट्रा-कारपोरेट ट्रांसफरीज' का कोटा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। टेंडर के आधार पर सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए समय की अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर दो साल कर दिया गया है। आइटी, बिजनेस सर्विसेज, आडियो-विजुअल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भारतीय कंपनियां अब ओमान में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर सकेंगी। एफटीए लागू होने के बाद भारत के उत्पाद और सेवा निर्यात ओमान में बढ़ सकेंगे और भारत का प्रतिकूल व्यापार असंतुलन कम होगा। ओमान के आधुनिक बंदरगाहों के उपयोग से पूर्वी यूरोप तक माल पहुंचाने में लगने वाले समय और खर्च में भारी कमी आएगी, जिससे भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ेगी।

मोदी सरकार के तौरान मारीशस, संयुक्त अरब अमीरात और आस्ट्रेलिया के साथ एफटीए पर प्रगति हुई है। एक अक्टूबर से भारत और चार यूरोपीय देशों आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नार्वे और लिंचेस्टाइन के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (एफ्टा) के बीच भी एफटीए लागू हो गया है और एफ्टा देशों को निर्यात बढ़ने लगे हैं। इसी क्रम में भारत और ब्रिटेन का एफटीए भी महत्वपूर्ण है। अब नए वर्ष 2026 में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन पेरू, चिली, आसियान, मेक्सिको, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इजरायल, भारत-गल्फ कंट्रीज काउंसिल सहित अन्य प्रमुख देशों-पक्षों के साथ भी एफटीए आकार लेते हुए दिखाई देंगे। इन देशों के साथ एफटीए में सिर्फ उत्पाद निर्यात ही शामिल नहीं होंगे, वरन सेवा सेक्टर परिदृश्य से संबंधित निर्यात भी शामिल होंगे। चूंकि सेवा निर्यात में भारत की विशेषज्ञता बढ़ती जा रही है, इसलिए जहां भारत के प्रशिक्षित श्रमिकों एवं पेशेवरों के लिए एफटीए वाले देशों में काम के मौके बढ़ेंगे, वहीं भारत की सेवा निर्यात से कमाई की ऊंची संभावनाएं बढ़ेंगी।

भारत के लिए एफटीए के लाभों के मद्देनजर एक अप्रैल से लागू होने वाले नए श्रम कानून मील का पत्थर साबित होंगे। केंद्र सरकार ने जिन बहुप्रतीक्षित चार नई श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया है, उनसे श्रमिकों के साथ उद्योग-कारोबारों को भी राहत मिलेगी। ये श्रम कानून स्वतंत्रता के बाद से सबसे व्यापक और प्रगतिशील श्रम-उन्मुख सुधार हैं। नए श्रम कानून भविष्य के लिए एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे, जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और इससे उद्योग-कारोबार को एफटीए के अधिकतम लाभ हासिल होने की उम्मीद बनी है।

नए वर्ष 2026 में भारत दुनिया के प्रमुख देशों के साथ एफटीए को तेजी से आकार देने की डगर पर आगे बढ़ेगा। उम्मीद करें कि नए साल में होने वाले एफटीए भारत को निर्यात, सेवा, निवेश, तकनीकी सहयोग और पेशेवरों की आवाजाही की नई आर्थिक शक्ति बनाते हुए देश को वर्ष 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की डगर पर आगे बढ़ाएंगे।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8

विश्व की दिशा परिवर्तन का वर्ष

शिवकांत शर्मा

ट्रंप की नाटकीय नीतियों से वैश्विक स्तर पर ऐसी उथल-पुथल मची जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही विश्व व्यवस्था में पहले कभी नहीं देखी गई

विश्व आर्थिक मंच, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, राजनयिक और विश्लेषक वर्ष 2025 को दुनिया की दिशा बदलने वाले वर्ष के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। इसकी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नाटकीय टैरिफ नीति, वैश्विक समीकरणों और व्यवस्थागत नियमों में हुई ऐसी उथल-पुथल है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही विश्व व्यवस्था में पहले कभी नहीं देखी गई। वैश्वीकरण के दौर में विश्व व्यापार बढ़कर 40 गुना से अधिक हो गया था जिसके कारण दुनिया के एक अरब से अधिक लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकल सके, लेकिन इस दौर में उद्योग-धंधे अमेरिका और यूरोप छोड़कर एशियाई देशों में चले गए, जहां कच्चा माल और मजदूरी सस्ती थी। इससे अमेरिका और यूरोप में कामगार बेरोजगार हुए और व्यापार घाटे भी बढ़े। ट्रंप इसी प्रक्रिया को पलटने के वादे पर चुनाव जीते थे। इसलिए उन्होंने सत्ता संभालते ही कुछ देशों पर भारी टैरिफ लगाने के साथ-साथ छोटे-बड़े सभी देशों पर टैरिफ लगा दिए। इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लगाया गया, ताकि विश्व व्यापार संगठन में चुनौती न दी जा सके। पिछले 70 वर्षों से मुक्त व्यापार की वकालत करते आ रहे देश ने 30 वर्ष लंबी गैट वार्ताओं के बाद बनी विश्व व्यापार की व्यवस्था को एक एलान से ध्वस्त कर दिया।

ट्रंप के टैरिफ युद्ध का प्रमुख निशाना चीन था, परंतु उसने अपने दुर्लभ खनिजों और औद्योगिक चुंबकों के ब्रह्मास्त्र से अपना बचाव कर लिया। भारत और ब्राजील इसके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए दोनों पर सर्वाधिक ऊंचे 50 प्रतिशत टैरिफ लगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि रूस पर युद्धविराम का दबाव डालने के लिए ट्रंप भारत पर रूसी तेल खरीदना बंद करने का दबाव डाल रहे हैं, जिसे वे दोस्त कहते हैं। जबकि रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार और प्रतिद्वंद्वी चीन से कुछ नहीं कहते। नाटो में अपने सहयोगी तुर्किये से कुछ नहीं कहते। अपने दोस्त हंगरी के नेता ओर्बान को खरीदने की छूट दे रहे हैं और खुद रूस से परमाणु ईंधन की खरीदारी जारी है। ट्रंप की अबूझ नीतियों के कारण यह साल 25 वर्षों से घनिष्ठ होते आ रहे भारत-अमेरिका रिश्तों पर संदेह और अनिश्चितता के साए का साल रहा।

इस नियमहीन धौंस की कूटनीति ने चीन, रूस और ब्राजील जैसी ब्रिक्स शक्तियों को डालर के बिना व्यापार करने के उपाय खोजने पर विवश किया। ये

अवधेश राजपूत

देश अब अपना अधिकांश व्यापार अपनी मुद्राओं में करने लगे हैं। रूस और चीन करीब 250 अरब डालर के व्यापार का 99.1 प्रतिशत अपनी मुद्राओं में करते हैं। भारत-रूस भी अपने व्यापार का 96 प्रतिशत अपनी मुद्राओं में करते हैं। चीन और ब्राजील भी आपसी व्यापार अपनी मुद्राओं में करने लगे हैं।

ट्रंप की नीतियों की अस्थिरता और अप्रत्याशितता ने सामरिक समीकरणों को भी उलटा-पलटा है। यूरोप के साथ अमेरिका के रिश्तों की बुनियाद सदियों पुरानी है। दूसरे महायुद्ध में यूरोप के जर्जर और कंगाल हो जाने के बाद अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी सामरिक और आर्थिक शक्ति बनकर उभरा था। इसलिए उसने अपने नेतृत्व में विश्व के लिए एक नई नियमबद्ध व्यवस्था बनाई जो उसके उदार लोकतंत्र, खुली स्पर्धा वाली आर्थिकी और कानून व्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित थी। यूरोप उसका सामरिक साथी और वैचारिक प्रयोगशाला बना। यूरोप ने शीतयुद्ध के दौरान साम्यवादी एकदलीय तानाशाही के फैलाव को रोके रखा। सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए पूर्वी यूरोप के देशों ने अमेरिका और यूरोप की व्यवस्था को केवल तेज आर्थिक विकास के लिए ही नहीं अपनाया था। उन्हें साम्यवादी तानाशाही से अपना अस्तित्व भी बचाना था और उम्मीद थी कि यूरोप और अमेरिका उनकी रक्षा करेंगे। ट्रंप यूक्रेन के बचाव की जगह पुतिन को खुश रखने के लिए जिस तरह उसकी जमीन और सुरक्षा का सौदा करने में लगे हैं, उसने इस भ्रम को भी तोड़ दिया है।

यूरोप को बड़ा धक्का ट्रंप की नई सुरक्षा नीति में पुतिन के हमले और तानाशाही की आलोचना की जगह अपनी आलोचना को पढ़कर लगा है। अमेरिकी सुरक्षा नीति कहती है कि लचर नीतियों के कारण यूरोप के कुछ देशों में कुछ ही दशकों के भीतर यूरोपीय सभ्यता लुप्त हो जाएगी, क्योंकि उसके उदार लोकतंत्र, खुली स्पर्धा वाली गैर-यूरोपीय बहुसंख्यक बन जाएंगे। इसलिए वह यूरोप में राष्ट्रवादी पार्टियों को सत्ता में देखना चाहती है। स्पष्ट है कि ट्रंप यूरोप को अब एक बोझ के सिवा कुछ नहीं मानते। दूसरी तरफ पुतिन का स्वागत वे महाशक्ति की तरह तालियां बजाकर करते हैं। चीनी राष्ट्रपति के साथ होने वाली शिखर बैठक को जी-2 की संज्ञा देकर वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि चीन अब बराबर की महाशक्ति है।

स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ट ने ट्रंप के इस रवैये को अमेरिका की 'सभ्यतागत आत्महत्या' की संज्ञा दी है। उदार लोकतंत्र, खुली स्पर्धा और नियमबद्ध व्यवस्था जैसे आदर्शों को ताक पर रखकर ट्रंप तीन महाशक्तियों के दबदबे वाली दुनिया बनाने की राह पर हैं। संयुक्त राष्ट्र के किसी मंच पर अब जुबानी जमाखर्च के सिवा इन तीनों को आमराय के बिना कुछ हो पाने की संभावना कम ही दिखती है। ऐसे में असली चुनौती यूरोप और भारत के सामने है कि कैसे अपनी सुरक्षा में आत्मनिर्भर होकर अपना दबदबा बढ़ाएं और कारोबार फैलाएं। इसमें कोई बड़ी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि दुनिया तिकोना रूप लेती है तो समर्थन-शक्ति के लिए कई छोटे देश साथ आना चाहेंगे। तीन या अधिक धुरियों में बंटी दुनिया में जलवायु परिवर्तन और जिहादी आतंक की रोकथाम जैसी वैश्विक चुनौतियों पर अब क्षेत्रीय सहयोग जुटाना अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा इस वर्ष का सबसे बड़ा दिशा परिवर्तन एआइ या यंत्रमेधा का आर्थिक गतिविधि के हर क्षेत्र में सक्रिय हो जाना है। 30 वर्ष पुरानी सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के बाद यह उससे भी बड़ी क्रांति है, जो खोज से लेकर निर्माण और उपभोग तक उत्पादन के हर पहलू को और कामकाज को प्रभावित करेगी।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8

हां 75% / नहीं 25% — क्या वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल पर देशव्यापी रोक जरूरी है?

हां 85% / नहीं 15% — क्या वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जरूरी कदम नहीं उठा रही हैं?

मुद्दा से संबंधित अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया mudda@jagran.com पर भेज सकते हैं।

कोयला एक नीति दो !

कोयले का उपयोग हवाओं को जहरीला बनाने के साथ जलवायु परिवर्तन की गति को भी तेज करता है। यह सर्वमान्य तथ्य है। यही वजह है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच कोयला,लकड़ी और जैविक कचरे को जलाने पर रोक लगाई गई है। इसका मतलब है कि सरकार कोयले के हानिकारक प्रभाव को समझती है। यहीं, पर सरकार की नीतियों के स्तर पर विरोधाभास दिखता है। दिल्ली में कोयला, लकड़ी और जैविक कचरा जलाने पर रोक लगती है,वहीं देश के बाकी हिस्सों में ऐसी कोई रोक नहीं है। विशेषज्ञ लंबे समय से इस बात की वकालत कर रहे हैं कि देश में वायु प्रदूषण की समस्या को एक शहर या राज्य विशेष की समस्या मान कर नहीं निपटा जा सकता है। इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक एक्शन प्लान बना कर उसे कड़ाई से लागू करना होगा। सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए हैं। खाना बनाने के लिए लकड़ी के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार उज्वला योजना लेकर आई लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर आबादी के लिए सिलिंडर रीफिल कराना आसान नहीं है। ग्रामीण इलाकों में खाना बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग अब भी हो रहा है। वायु प्रदूषण से निपटने में सरकार की नीतियों में विरोधाभास की पड़ताल ही आज का अहम मुद्दा है...

खाना बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल

41% भारतीय परिवार अब भी खाना बनाने के लिए जलाते हैं लकड़ी, उपले या दूसरे बायोमास

34 करोड़ टन कार्बन डाईआक्साइड का सालाना उत्सर्जन होता है लकड़ी और उपले जलाने से

13% हिस्सा है यह उत्सर्जन भारत के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का

50 करोड़ भारतीय अब भी वंचित है स्वच्छ ऊर्जा समाधान से

6 लाख मौतें होती हैं सालाना घर के अंदर के प्रदूषण से

भारत में जीवाश्म ईंधन की खपत

भारत में जीवाश्म ईंधन की खपत काफी ज्यादा है। यह कुल ऊर्जा की जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत है। इसमें कोयला सबसे प्रमुख है, जो बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है। हालांकि स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी तेज़ी से बढ़ रही है। 2023 में स्वच्छ ऊर्जा की खपत 8 प्रतिशत बढ़ी, और सरकार जैव-ईंधन को बढ़ावा दे रही है।

मुख्य बिंदु

बढ़ती खपत: 2023 में भारत में जीवाश्म ईंधन की खपत 8 प्रतिशत बढ़ी, और यह लगभग सभी ऊर्जा मांग वृद्धि के लिए ज़िम्मेदार थी।

कोयले का प्रभुत्व: देश की बिजली जरूरतों का बड़ा हिस्सा लगभग 55-75 प्रतिशत कोयले से पूरा होता है, जो भारत का सबसे प्रचुर जीवाश्म ईंधन है।

ऊर्जा मिश्रण : 2023 में, कुल ऊर्जा आपूर्ति में कोयले की हिस्सेदारी 46 प्रतिशत, तेल की 25 प्रतिशत, और प्राकृतिक गैस की 5 प्रतिशत थी।

वैश्विक स्थिति : 2023 में चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जीवाश्म ईंधन उपभोक्ता था।

नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि: स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ रही है। 2025 के मध्य तक, कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक गैर-जीवाश्म स्रोतों (नवीकरणीय ऊर्जा सहित) से था।

सरकारी प्रयास : सरकार जैव-ईंधन जैसे इथेनाल, बायोडीजल) के उपयोग को बढ़ावा दे रही है ताकि आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सके और पांच साल में खपत का 50 प्रतिशत जैव-ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य है। हालांकि वर्तमान में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ऐसे में भारत की ऊर्जा जरूरतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में निकट भविष्य में पूरी तरह से जीवाश्म ईंधन से छुटकारा पाना संभव नहीं होगा।

जागरण रिसर्च

जीवाश्म ईंधन जलाने से वैश्विक जीडीपी का 3.3 प्रतिशत नुकसान

गैस, कोयला और तेल जलाने से दुनिया भर में सड़क हादसों से होने वाली मौतों की तुलना में तीन गुना ज्यादा मौतें होती हैं। 2018 में इसका वैश्विक आर्थिक नुकसान 2.9 लाख करोड़ डालर था, जो वैश्विक जीडीपी का 3.3 प्रतिशत है। अनुमान है कि 2018 में वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से 45 लाख की मौत हुई, जबकि पीएम 2.5 प्रदूषण की वजह से 1.8 अरब दिनों की काम से छुट्टी, बच्चों में अस्थमा के 40 लाख नए मामले और 20 लाख बच्चों का जन्म समय से पहले हुआ।

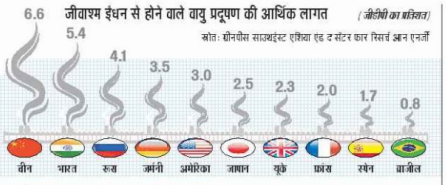

जीवाश्म ईंधन से होने वाले वायु प्रदूषण की आर्थिक लागत

(जीडीपी का प्रतिशत)

स्रोत: ग्रीनपीस साउथईस्ट एशिया एंड द सेंटर फार रिसर्च आन एनर्जी

चीन	भारत	रूस	जर्मनी	अमेरिका	जापान	यूके	फ्रांस	स्पेन	ब्राजील
6.6	5.4	4.1	3.5	3.0	2.5	2.3	2.0	1.7	0.8

चुनौतियां और भविष्य

भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग और विकास के कारण, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता एक बड़ी चुनौती है। हालांकि स्वच्छ ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है। सरकार और उद्योग इलेक्ट्रिक वाहन (इवी) और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि जीवाश्म ईंधन की खपत को कम किया जा सके।

17 लाख भारतीयों की मौत हुई 2022 में भारत में जीवाश्म ईंधन से होने वो प्रदूषण की वजह से

प्रदूषित हवा से देशों को नुकसान

देश	(अरब डालर में)
चीन	900
अमेरिका	600
भारत	150

एलपीजी सिलिंडर रीफिल कराने की चुनौती

10 करोड़ परिवारों को नया एलपीजी सिलिंडर मिला था उज्वला योजना के तहत 2023 तक

1/3 आय खर्च करनी होगी बीपीएल परिवारों को एलपीजी सिलिंडर रीफिल कराने पर

50% परिवारों ने एक बार भी रीफिल नहीं कराया है सिलिंडर ऊंची लागत की वजह से

₹1,100 औसत लागत है एलपीजी सिलिंडर रीफिल कराने की भारत में

₹8,800 खर्च आएगा एक परिवार को पूरे वर्ष सिलिंडर रिफल कराने पर

₹27,000 सालाना औसत आय की सीमा तय की गई गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए नीति आयोग

उत्तर भारत में लागू हों निवारक कदम

अनुमिता राय चौधरी
कार्यकारी निदेशक, सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट

वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए हमें पूरे वर्ष समस्या पैदा करने वाले कारणों को खत्म करने पर काम करना होगा। कदम पूरे उत्तर भारत में उठाने होंगे। प्रदूषण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। सिर्फ दिल्ली में कोयला और कचरा जलाने पर रोक से प्रभावी समाधान नहीं मिलेगा।

दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को एक क्षेत्र विशेष की समस्या मानकर इससे नहीं निपटा जा सकता है। हमें यह समझना होगा कि पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण की गंभीर स्थिति एक खास भौगोलिक स्थिति के कारण है। यह पूरे इंडो गैंग्नेटिक प्लेन यानी उत्तरी मैदान की समस्या है। ठंड में प्रदूषण की स्थिति इसलिए गंभीर हो जाती है क्योंकि हवा का प्राकृतिक वेंटिलेशन रुक जाता है। ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ यहीं सीमित है। यह पूरे एनसीआर क्षेत्र और आस पास के दूसरे प्रदेशों में भी फैलता है। इसी तरह से दूसरे प्रदेशों का प्रदूषण भी दिल्ली तक आता है। दिल्ली के प्रदूषण में उसका योगदान सिर्फ 30 प्रतिशत है। बाकी प्रदूषण का स्रोत दिल्ली से बाहर है। ऐसे में प्रदूषण की समस्या को खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले पूरे उत्तर भारत के शहरों के हाटस्पाट यानी ऐसी जगहें जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण है, वहां से शुरुआत करनी होगी। इसके बाद शहरों और रीजन के हिसाब से कदम उठाने होंगे। सिर्फ दिल्ली में कोयला, लकड़ी और जैविक कचरा जलाने पर रोक लगाना एक तात्कालिक कदम है लेकिन हमें पूरे उत्तरी मैदान के हिसाब से एक्शन प्लान बना कर उस पर अमल करना होगा। अगर कोयला लकड़ी और जैविक कचरे के जलने से दिल्ली की हवा प्रदूषित हो रही है तो यही प्रदूषण देश के बाकी हिस्सों में भी हो रहा है। ऐसे में जब तक हम पूरे रीजन में जीवाश्म ईंधन की जगह स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक प्रदूषण की समस्या से प्रभावी तरीके से नहीं निपटा जा सकता है। यह सही है कि बिजली उत्पादन के लिए हमें कोयले की जरूरत है लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने पावर प्लांट को धीरे धीरे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर ले जाएं। इसी तरह जैविक कचरा न जलाया जाए। इसके लिए हमें पूरे देश में घरों से निकलने वाले कचरे को एकत्र करके इससे बायोगैस या दूसरी चीजें बनाने का एक मजबूत तंत्र विकसित करना होगा। सिर्फ कुछ शहरों में कचरा प्रबंधन करके काम नहीं चला सकते हैं। अब बात आती है कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पूरे वर्ष काम करने की। आम तौर पर जब प्रदूषण की बात आती है सिर्फ दिल्ली की बात होती है और वह भी ठंड के कुछ महीनों की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंड के दिनों में प्रदूषण धुंध के रूप में हमें दिखने लगता है जबकि दिल्ली में पूरे वर्ष का एक्यूआइ 126 है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के हिसाब से पूरे वर्ष का एक्यूआइ 40 होना चाहिए। इसका मतलब है कि पूरे वर्ष दिल्ली में प्रदूषण मानक से चार पांच गुना अधिक रहता है। इसका मतलब है कि हमें प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पूरे वर्ष काम करना होगा और प्रदूषण से प्रभावित पूरे रीजन यानी उत्तर भारत में काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है लेकिन जितने बड़े पैमाने पर और जितनी तेजी से काम होना चाहिए, उस तरह से काम नहीं हो रहा है। राज्यों को सार्वजनिक परिवहन की दिशा में बड़े पैमाने पर काम करना होगा, जिससे लोग आसानी से आ जा सकें और सड़कों पर निजी गाड़ियों की संख्या कम हो। ग्रामीण इलाकों में खाना बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल अब भी हो रहा है। सरकार को इस दिशा में भी ध्यान देना चाहिए। आप सिर्फ शहरों में कदम उठा कर प्रदूषण से नहीं निपट सकते हैं क्योंकि अगर ग्रामीण इलाकों में प्रदूषण हो रहा है यह शहरों तक जरूर आएगा।

आपकी आवाज

दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण का एक इलाज यह भी है कि यहां ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक वाहनों खासतौर पर मैट्रो का विस्तार भी है। सरकार को चाहिए कि इसके लिए प्राथमिक और युद्धस्तर पर का करें और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए, आम्जन को भी चाहिए कि वो सार्वजनिक वाहनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, अपने वाहन का प्रयोग जरूरी होनेही करें।
राजेश कुमार चौहान

वायु प्रदूषण आज देश की सबसे गंभीर स्वास्थ्य आपदाओं में से एक बन चुका है। केंद्र और राज्य सरकारें योजनाएं तो बना रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार नजर नहीं आ रहा है। न तो नियमों का पालन हो रहा है, न ही प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्ती हो रही है। हर साल हालात बदतर होते जा रहे हैं और आम नागरिक इसकी कीमत चुका रहा है। अब सवाल सिर्फ कदम उठाने का नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने का है। **साहिल गर्ग**

वायु प्रदूषण का एक कारण पेट्रोल और डीजल वाहन भी हैं। अगर देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिले तो यह वायु प्रदूषण रोकने के लिए अच्छी पहल होगी। हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण भी वाहनों में भी वृद्धि हुई है। अगर बढ़ते प्रदूषण के लिए सरकारों के साथ आमजन अभी भी गंभीर नहीं हुआ तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा। हमारे देश के लिए यह अच्छा संकेत है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन शुरू हो चुका है। दीपक पांडे

इंडस्ट्री को बनाया जाए गैस आधारित

डी साहा
पूर्व अतिरिक्त निदेशक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

जीवाश्म ईंधन हमारी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने में बड़ा योगदान करता है। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए इंडस्ट्री और पावर प्लांट को गैस आधारित बनाना होगा। इसके अलावा हमें स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना होगा। इससे हमारे ऊर्जा के मिश्रण में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ेगी।

ऐसे समय में जब प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसके स्रोत पर ही लगाम लगानी होगी। ऐसे में यह देखा जाता है कि प्रदूषण के जिन स्रोतों को बंद करने से आम जन जीवन बाधित न हो, उसी के हिसाब से सरकार कदम उठाती है। अब बात आती है कोयला, लकड़ी या दूसरे बायोमास जलने की तो इसके जलने से हवा में जहरीले तत्वों की मात्रा बढ़ती है और प्रदूषण की स्थिति और गंभीर हो जाती है।

ऐसे में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इस पर रोक लगाना एक प्रभावी कदम है। हालांकि यह बात सही है कि प्रदूषण को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है क्योंकि हवा बहती है और हवा किसी भौगोलिक या राजनीतिक सीमा में सीमित नहीं रहती है। इसका मतलब है कि अगर दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पर काबू पाना है तो कम से कम पूरे एनसीआर में निवारक कदम उठाए जाने चाहिए। ये कदम सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं होने चाहिए। दूसरी समस्या खाना बनाने में लकड़ी उपले और दूसरे बायोमास के इस्तेमाल की है। केंद्र सरकार की उज्वला योजना से एक बड़ी आबादी तक खाना बनाने के लिए एलजीपी सिलिंडर तक पहुंच सुनिश्चित हुई लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एलपीजी सिलिंडर की लागत को वहन करना एक चुनौती है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी एलपीजी सिलिंडर रीफिल करा सकें, इसके लिए सब्सिडी की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी ग्रामीण इलाकों में प्रदूषण की समस्या को लेकर ज्यादा बात नहीं होती है लेकिन अगर कहीं भी लकड़ी या बायोमास जलता है तो जहरीले तत्व वातावरण को प्रदूषित करते हैं और इसका असर शहरों पर भी पड़ता है। कोयला और दूसरे जीवाश्म ईंधन हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरी करते हैं। हमारे देश में ज्यादातर पावर प्लांट कोयले से चलते हैं। इनको धीरे धीरे गैस पर चलाना होगा। हालांकि इसे एक साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए हर प्लांट में तकनीकी बदलाव करने होंगे। एक साथ करने से कई तरह की व्यावहारिक दिक्कते आ सकती हैं। ऊर्जा की आपूर्ति बाधित हो सकती है। ऐसे में एक प्लान बना कर इंडस्ट्री को गैस आधारित करना होगा। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना होगा। इससे हमारे ऊर्जा मिश्रण में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी कम होगी और प्रदूषण में कमी के साथ आयातित जीवाश्म ईंधन की जरूरत भी कम होगी। तीसरी बड़ी समस्या कचरा जलने की है। इससे भी प्रदूषण बढ़ता है। इसके लिए गांव से लेकर शहर तक प्रभावी कचरा प्रबंधन करना होगा। आज के समय में ऐसी तकनीक उपलब्ध है, जिससे हम कचरे से गैस और बिजली बना सकते हैं। इसके लिए स्थानीय स्तर पर पहल करते हुए गांव में पंचायत स्तर पर कचरे से गैस या बिजली बनाने वाले प्लांट लगाए जा सकते हैं। इससे बनने वाली गैस या बिजली से स्थानीय स्तर पर बिजली की जरूरत पूरी की जा सकती है। यही माडल कस्बों या शहरों में लागू किया जा सकता है। इस तरह से हम प्रदूषण के स्रोत को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्ययोजना बना कर उस पर प्रभावी तरीके से अमल करने की। हमारे देश में कार्ययोजना भी है लेकिन इस पर कितना काम हो रहा है और जमीनी स्तर पर किस हद तक बदलाव आया है इसको लेकर जवाबदेही की कमी है। जब तक जिम्मेदार एजेंसियों की जवाबदेही नहीं तय होगी तक जमीन पर बदलाव नहीं दिखाई देगा।

परमाणु बिजली नहीं, अक्षय ऊर्जा में ही भविष्य सुरक्षित

यहां स्कैन करें

पुष्परंजन | वरिष्ठ पत्रकार

नाम लंबा है- 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऐंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।' संक्षेप में- शांति। गुरुवार को संसद में जो सांसद इसका विरोध कर रहे थे, उन्हें 'शांत' रहने को कहा गया। सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों ने शांति मंत्र के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय पोखरण परमाणु परीक्षण को याद किया, तो कुछ ने 18 जुलाई, 2005 को अमेरिका से परमाणु समझौते को रेखांकित किया, जिसकी वजह से परमाणु व्यापार पर तीन दशक से चली आ रही अमेरिकी रोक हटी। फिर भी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और मनमोहन सिंह के दौर में हुआ 123 करार पूर्णतः लागू नहीं हुआ, तो उसकी वजह क्षतिपूर्ति के ढीले-ढाले प्रावधान थे। परमाणु दायित्व कानूनों में बंधना भारत को मंजूर नहीं था। भारत परमाणु संयत्रों में इस्तेमाल ईंधन पर पूरा हक चाहता था। अमेरिकी दबाव से हम मुक्त न थे। भारतीय संसद से पारित 'शांति' विधेयक अमेरिकी बाधा-बंधन से दूर है।

परमाणु ऊर्जा के पक्ष की बात करें, तो यह कम लागत वाला ऊर्जा स्रोत है। यह विश्वसनीय है और उद्योग के अवसर व रोजगार सृजित करता है। इससे शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है और इसका ऊर्जा घनत्व भी उच्च है, लेकिन इसकी कमियों पर भी गौर कीजिए। इसमें पानी की अत्यधिक खपत होती है और रेडियोधर्मिता जैसी परमाणु दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। सबसे बड़ी चुनौती परमाणु कचरे का प्रबंधन है। साल 2023 में अपने आखिरी विद्युत केंद्र बंद करने के बावजूद जर्मनी अभी भी 27,000 क्यूबिक मीटर रेडियोएक्टिव कचरे को स्टोर करने के लिए स्थायी जगह ढूंढ़ रहा है। यह स्थिति किसी भी परमाणु ऊर्जा वाले देश की 'स्टोरेज' व 'ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी' के बारे में जरूरी सवाल उठाती है। जर्मनी में तो नाभिकीय कचरे के निष्पादन के लिए 23.6 बिलियन यूरो का एक कोष बना हुआ है। क्या भारत ऐसा कर पाएगा?

इसमें पानी की अत्यधिक खपत होती है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। सबसे बड़ी चुनौती तो परमाणु कचरे का प्रबंधन है।

परमाणु संयंत्र में दुर्घटना और उसका विनाशकारी असर एक बड़ा सवाल है। हम ऐसा कुतर्क नहीं कर सकते कि सड़क दुर्घटना के डर से गाड़ी चलाना छोड़ दें क्या? हम भोपाल गैस कांड के साक्षी हैं। हम फुकुशिमा, चेर्नोबिल और पेंसिल्वेनिया की थ्री माइल आइलैंड जैसी भयावह घटनाओं से आंख मूंद नहीं सकते। 'शांति विधेयक' का कमजोर पक्ष यह है कि अगर किसी परमाणु बिजली ऑपरेटर की लापरवाही से विनाश होता है, तो प्रभावित समुदाय कोर्ट में शिकायत नहीं करवा सकता।

भारत में सभी वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा किया जाता है। इस समय भारत के सात राज्यों में 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कार्यरत हैं, जिनकी स्थापित क्षमता 6,780 मेगावाट है। भारत अपने कुल ऊर्जा उत्पादन का मात्र 3.1 प्रतिशत परमाणु संयंत्रों से हासिल करता है। सरकार ने हाल में जानकारी दी है कि 2031-32 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़कर 22,480 मेगावाट हो जाएगी। यहां सवाल है कि जर्मनी जैसा विकसित देश क्यों परमाणु ऊर्जा से दूर हो गया? मार्च 2025 में जर्मनी की पर्यावरण मंत्री स्टेफी लेम्के ने इसकी वजह दोहराई थी कि 'परमाणु ऊर्जा के खतरे आखिर में बेकाबू होते हैं, इसीलिए इसे हटाने से हमारा देश ज्यादा सुरक्षित व परमाणु कचरे से बचता है।'

परमाणु ऊर्जा संयंत्र 31 देशों में हैं। अमेरिका में 94 परमाणु बिजलीघर हैं। बावजूद इसके, वहां परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत है, जबकि प्राकृतिक गैस का हिस्सा 40 फीसदी से अधिक है, इसके बाद अक्षय ऊर्जा (23 प्रतिशत) व कोयले (16 फीसदी) का स्थान रहा है। फ्रांस में 55 और चीन में 58 परमाणु बिजलीघर हैं। भारत, दुनिया का चौथा पवन ऊर्जा निर्माता व तीसरा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन चुका है। हम अपने संसाधनों के दोहन में जुट जाएं, तो नंबर एक बन सकते हैं। 2047 तक भारत का लक्ष्य बिजली क्षमता को 2,100 गीगावाट करना है, जिसमें परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी केवल 100 गीगावाट है। यदि यह सही है, तो अन्य स्रोतों से उत्पादित 2,000 गीगावाट विद्युत के आगे कुछ भी नहीं है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, फिलहाल भारत की 50.07 प्रतिशत बिजली अक्षय ऊर्जा से आता है। इससे जान-माल, प्रदूषण और रेडिएशन का कोई जोखिम नहीं है। हमें इसी दिशा में बढ़ना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)